

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत | 80 दिनों का सत्र | बैंगलूर और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित



5 'पर्यटन को सांस्कृतिक पुनर्जागरण और रोजगार सृजन से जोड़कर आगे बढ़ाएं'

6 ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा स्ट्रीट फाइट का किला

7 जब हैसियत बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं : कंगना रनौत

फास्ट टैक

पाकिस्तान की तेल एवं गैस कंपनी ने सिंध प्रांत में तेल भंडार की खोज की क्रावी/भाषा। पाकिस्तान की सरकारी तेल एवं गैस कंपनी ने देश के सिंध प्रांत के संघर जिले में तेल और गैस भंडार की बड़ी खोज की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओजीडीसीएल) ने बताया कि इस खोज से देश की ऊर्जा मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को घरेलू संसाधनों के जरिए कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। साथ ही कंपनी और देश के हाइड्रोकार्बन भंडार आधार में भी वृद्धि होगी। कंपनी ने पाकिस्तान शेयर बाजार और लंदन शेयर बाजार को भी सूचना में कहा कि पिछले महीने संघर जिले के बोधी और धमरा की क्षेत्रों में यह खोज की गई।

असम मंत्रिपरिषद विस्तार: आज 12 मंत्री शपथ लेंगे गुवाहाटी/भाषा। असम मंत्रिपरिषद का शुक्रवार को विस्तार किया जाएगा जिसमें तीन नए चेहरों सहित 12 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने यह घोषणा की। नए चेहरों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अश्विनी र सरकार, नीलमा देवी और सुशांत बोरगोहेन शामिल हैं। असम गण परिषद (आप) के केशव महंत को भी मंत्रियों की सूची में शामिल किया गया है। वह पिछली राजग सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। पिछली विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत देवारी का नाम भी नए मंत्रियों की सूची में शामिल है। शेष लोग शर्मा की पहली मंत्रिपरिषद में शामिल थे और वे भाजपा के नेता हैं। इनमें अशोक सिंघल, रनोज पेपु, विमल बोरा, जयंत मल्ला बरुआ, कौशिक राय, कुण्डू पॉल और पीपूष हजारा का नाम है।

पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई, दो लोग गिरफ्तार
चंडीगढ़/भाषा। राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (एसएसओसी) एसएस नगर (मोहाली) ने सीमा पार आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए विदेश स्थित एक आतंकीवादी के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से पूरी तरह से तैयार आरडीएस आधारित संघर्षित विस्फोटक उपकरण (आईईडी) बरामद कर एक आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। गिरफ्तार किए गए लोगों में अमृतसर के गुजरपुरा निवासी मणि सिंह (32) और अमृतसर के गिलवाली गेट निवासी अभिषेक कुमार (28) शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि बरामद किया गया लगभग 2.5 किलोग्राम आईईडी पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए तैयार था।

पूर्वोत्तर में उग्रवाद अब कोई बड़ा मुद्दा नहीं : अमित शाह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

शिलांग/भाषा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद अब कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने क्षेत्र की राज्य सरकारों से कानून-व्यवस्था तक सीमित रहने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा तथा उभरती प्रौद्योगिकियों और नए आर्थिक क्षेत्रों के माध्यम से विकास को गति देने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।



यहां उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के 73वां पूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पिछले एक दशक में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है, जहां अशांति की जगह शांति ने ले ली है और विकास और निवेश के नए रास्ते खुल गए हैं। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, पूर्वोत्तर में उग्रवाद

अब कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। राज्य सरकारों का ध्यान अब केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित न रहकर नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित होना चाहिए कि विकास का लाभ हर घर तक पहुंचे।

मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन ओलंपिक में जगह बनायेगा : मोदी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैम्पियनशिप को योग के नये चरण का शुभारंभ बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि भविष्य में योगासन ओलंपिक समेत अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में अपनी जगह बनायेगा।



अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैम्पियनशिप की शुरुआत की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बर्चुअल भाषण में कहा, "अहमदाबाद की धरती से विश्व की खेल विरासत में एक और नया अध्याय जुड़ा है। पहली विश्व योगासन चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने आये सभी देशों के खिलाड़ियों का भारत में स्वागत करता हूँ।" उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतरराष्ट्रीय खेलों

में अपनी जगह बनायेगा। ओलंपिक हो या बहुखेल आयोजन हो, निश्चित तौर पर अहमदाबाद में होने वाली पहली योगासन विश्व चैम्पियनशिप की इसमें बड़ी भूमिका होगी।" अहमदाबाद में हो रही इस चैम्पियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 122 सदस्यीय दल उतारा है जिसमें खिलाड़ी छह वर्ग में मुकाबला करेंगे। ये खिलाड़ी पांच दिन में

दुनिया के पास संतुलित प्रगति के लिए कोई उपाय नहीं : भागवत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने बृहस्पतिवार को कहा कि दुनिया के पास ऐसा कोई मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, जो मानव जीवन के कई आयामों में एक साथ प्रगति सुनिश्चित कर सके। भागवत ने कहा कि वैश्विक व्यवस्थाएं व्यक्तिगत कल्याण, सामाजिक हितों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने को लेकर अब भी दुविधा में फंसी हुई हैं। नागपुर में आरएसएस के स्वयंसेवी प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि दुनिया मानव शरीर, मन और बुद्धि का अलग-अलग विकास करना जानती है, लेकिन वह एक ऐसा ढांचा विकसित करने में विफल रही है, जो इन तीनों का एक साथ विकास कर सके। उन्होंने कहा, दुनिया मानव शरीर के



विकास के साथ-साथ मन और बुद्धि के विकास को भी जानती है। लेकिन दुनिया यह नहीं जानती कि इन तीनों मोर्चों पर प्रगति कैसे हासिल की जाए। मौजूदा वैश्विक संघर्षों का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा कि इनका असर उन देशों पर भी पड़ता है, जो सीधे तौर पर इनमें शामिल नहीं हैं। लेकिन वह एक ऐसा ढांचा विकसित के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। आरएसएस प्रमुख को कहा कि

आवश्यक हों, तो व्यक्ति के अधिकारों का दमन होता है। संघ प्रमुख ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भौतिक विकास अक्सर प्रकृति की कीमत पर किया जाता है, जबकि पर्यावरण संरक्षण को अक्सर विकास में बाधा के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा, भौतिकवादी विकास के लिए पर्यावरण का शोषण किया जाता है। और पर्यावरण की रक्षा के लिए (कुछ लोग मांग करते हैं कि) विकास रोक दिया जाए। दुनिया इस तरह के मुद्दों में फंसी हुई है और भ्रमित है। भागवत ने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, जो एक साथ सुख, शांति और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कर सके। उन्होंने कहा कि सिद्धांतों और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में समाधान मौजूद हो सकते हैं, लेकिन मानवीय आदतों और सीमाओं के कारण उनका कार्यान्वयन कठिन बना रहता है।

झारखंड के पलामू में मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतरे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मेदिनीनगर (झारखंड)/भाषा। झारखंड के पलामू जिले में कोयले से लदी एक मालगाड़ी के बृहस्पतिवार को कम से कम 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे के कारण डालटनगंज और गढ़वा रोड जंक्शन के बीच ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं। रेलवे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस घटना में किसी के हाताहत होने की सूचना नहीं है।

यह घटना पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) के धनबाद मंडल के अंतर्गत दोपहर करीब एक बजे राजहरा स्टेशन के पास हुई। इस हादसे के कारण कम से कम 10 यात्री ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन किया गया, उन्हें गंतव्य से पहले रोकना गया या रद्द कर दिया गया। पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) सरस्वती चंद्र ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, कोयले से लदे 15 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इस मार्ग पर लम्बी दूरी की दो मालगाड़ियां गुजर रही थीं, जिनमें करीब 116 डिब्बे थे।

टाटा स्टील के ब्रिटेन स्थित संयंत्र में लगी आग

नई दिल्ली/भाषा। टाटा स्टील के ब्रिटेन स्थित संयंत्र में बुधवार को आग लग गई। कंपनी ने बृहस्पतिवार को एक बयान में यह जानकारी दी। यह संयंत्र फिलहाल कम-कार्बन (लो-कार्बन) इस्पात उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव के दौर से गुजर रहा है। 'टाटा स्टील यूके' ने कहा, "सभी कर्मियों को सुरक्षित रूप से संयंत्र से निकाल लिया गया।" कंपनी ने बताया कि 'मिड एंड वेस्ट वेल्स फायर सर्विस' बुधवार रात करीब आठ बजे (स्थानीय समयानुसार) पोर्ट टैलबोट स्थित घटनास्थल पर आग बुझाने के लिए पहुंची।

05-06-2026 06-06-2026
सूर्योदय 6:43 बजे सूर्यास्त 5:52 बजे

BSE 74,360.01 (+13.84)
NSE 23,416.55 (+10.95)

सोना 16,074 रु. (24 कैर) प्रति ग्राम
चांदी 268,955 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी पत्रिका
epaper.dakshinbharat.com

केलाश मण्डेला, मो. 9828233434

न्यायिक पारदर्शिता
न्यायिक घरे के भीतर, विद्वानों का गणतंत्र।
तब ही सही फैसले लेना, सचमुच तय होगा।
हो सकता ना कोई निरंकुश, सत्य विजय होगा।
ऐसा लोकतंत्र दुनिया में, कभी न क्षय होगा।।

भारत और ब्रिटेन भविष्योन्मुखी साझेदारी बनाने के लिए अच्छी स्थिति में : जयशंकर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और ब्रिटेन अपने नवगठित व्यापक व्यापार समझौते तथा रक्षा औद्योगिक रोडमैप के आधार पर एक नयी भविष्योन्मुखी एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी के निर्माण के लिए अच्छी स्थिति में हैं। उन्होंने यह बात भारत यात्रा पर आई ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर के साथ हुई बैठक के दौरान कही।



विदेश मंत्री ने हाल के महीनों में द्विपक्षीय संबंधों में हुए 'उल्लेखनीय घटनाक्रमों' पर प्रकाश डालते हुए, गत जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा और उसके बाद अक्टूबर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर की भारत यात्रा का उल्लेख किया। जयशंकर ने भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (सीईटीए) को अंतिम रूप देने, व्यापक रणनीतिक

बढ़कर साझा आर्थिक महत्वाकांक्षाओं एवं उच्च प्रौद्योगिकी का एक भविष्योन्मुखी मार्ग बन गया है। विदेश मंत्री ने 'भारत-ब्रिटेन विजन 2035' और इसके पांच स्तंभों जैसे प्रगति, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा का भी उल्लेख किया। उन्होंने लिवरपूल विश्वविद्यालय द्वारा भारत में एक परिसर खोलने के निर्णय का भी उल्लेख किया। कूपर ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हाल के वर्षों में भारत-ब्रिटेन साझेदारी 'लगातार मजबूत' हुई है।

आमिर खान ने गौरी स्प्रेट से शादी की पुष्टि की, पांच जुलाई को शादी करेंगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। अभिनेता आमिर खान ने पुष्टि की है कि वह पांच जुलाई को अपनी साथी गौरी स्प्रेट से शादी करेंगे। बुधवार को कई खबरों में दावा किया गया कि आमिर और गौरी स्प्रेट अगले महीने एक बेहद निजी समारोह में शादी करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, अभिनेता ने इन अटकलों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। बृहस्पतिवार को आमिर ने इस खबर की पुष्टि की। आमिर ने 'वैरायटी इंडिया' को बताया, मैं फिलहाल अमेरिका में हूँ। शादी की खबर सच है। शादी पांच जुलाई को है। आमिर खान की यह तीसरी शादी होगी। उनकी पहली शादी फिल्म निर्माता रीना दत्ता से 1986 में हुई थी और 2002 तक चली थी। उनके दो बच्चे हैं - जुनेद और इरा खान। आमिर ने 2005 में निर्देशक किरण राव से शादी की और दोनों 2021 में अलग हो गए थे।

OPENS TODAY
A NEW CHAPTER IN
STYLE BEGINS

HI LIFE
EXHIBITION
Fashion | Style | Decor | Luxury
OVER 250+ OF TOP LABELS

5.6.7 JUNE
THE LaLIT
ASHOK BANGALORE
10 am - 8 pm | Valet Parking | Entry fee Rs.100



सरकारी नौकरी योग्य उम्मीदवारों को निर्धारित योग्यताओं के अनुसार ही मिलनी चाहिए : उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी नौकरी निर्धारित योग्यताओं के अनुसार योग्य उम्मीदवारों को ही मिलनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उच्च योग्यता वाले व्यक्ति को कम योग्यता वाले लोगों के लिए तय नौकरी प्राप्त करने की अनुमति देना वास्तव में योग्य और पात्र उम्मीदवार को वंचित करना है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमजुल्हाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने यह टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के उच्च आदेश को रद्द करते हुए की, जिसमें एक अस्थायी बैंक परिचालक की सेवा बहाल करने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि कर्मचारी ने स्नातक होने की बात छिपाकर उस पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी जो विशेष रूप से 10वीं कक्षा तक की योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था। पीठ ने कहा, "सरकारी नौकरी सभी पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित योग्यताओं के अनुसार ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए..." शीर्ष अदालत ने कहा, "जब उच्च पद विशेष रूप से कम शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए था, तो उच्च योग्यता वाले व्यक्ति को ऐसी नौकरी देना निश्चित रूप से वास्तव में एक योग्य और पात्र उम्मीदवार को अवसर से वंचित करने जैसा होगा।" शीर्ष अदालत ने कहा कि शैक्षणिक योग्यता की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के पीछे का उद्देश्य तर्कसंगत और न्यायसंगत है। इसका मकसद उन लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, जो जीवन की परिस्थितियों के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके।



खरगो राज्यसभा चुनाव के लिए आज दाखिल करेंगे नामांकन

बेंगलूर/नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगो शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। वह एक बार फिर से कर्नाटक से राज्यसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वह वर्तमान में भी अपने गृह प्रदेश से ही उच्च सदन के सदस्य हैं और 25 जून को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। वह राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि वह शुक्रवार को बेंगलूर में नामांकन दाखिल करेंगे। कर्नाटक की चार राज्यसभा और सात विधान परिषद सीट पर चुनाव के लिए अधिसूचना बीते सोमवार को जारी की गई, जिसके तहत मतदान 18 जून को होगा। राज्यसभा सदस्य के रूप में खरगो के अलावा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के इरफा कडाडी और नारायण कोराप्पा तथा जनता दल (एन) के एचडी देवेगौड़ा का कार्यकाल 25 जून को समाप्त होने वाला है, जिसके मद्देनजर इन चार सीट पर चुनाव कराए जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि आठ जून है। नामांकन पत्रों की जांच नौ जून को की जाएगी। वहीं, उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून है। मतगणना 18 जून को ही मतदान की समाप्ति के बाद की जाएगी। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के मद्देनजर सत्तारूढ़ कांग्रेस के राज्यसभा की चार सीट में से तीन और विधान परिषद की सात सीट में से पांच पर जीत हासिल करने की उम्मीद है।

अनिश्चितता के माहौल में लोग खर्च के बजाय बचत को दे रहे प्राथमिकता: रिपोर्ट

नई दिल्ली/भाषा। आर्थिक एवं वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय उपभोक्ता अपने खर्च को लेकर अब अधिक सतर्क हो गए हैं और बचत को प्राथमिकता दे रहे हैं। एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह निष्कर्ष पेश किया गया है। बाजार शोध फर्म कांफार की उपभोक्ता धारणा पर केंद्रित यह सर्वेक्षण रिपोर्ट कहती है कि लोगों का आर्थिक एवं व्यक्तिगत वित्तीय संभावनाओं को लेकर भरोसा कुछ कमजोर हुआ है, जिसकी वजह से वे खर्च के बजाय बचत बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं।

सर्वे में कहा गया है कि उपभोक्ता अब खर्च को लेकर अधिक चयनात्मक हो गए हैं और ऐसी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो लंबे समय में मूल्य प्रदान करें। मई महीने में किए गए इस अध्ययन में 21 से 55 वर्ष आयु वर्ग के 1,684 उपभोक्ताओं को शामिल किया गया, जिनमें महानगरों एवं गैर-महानगरों के लोग शामिल थे। हालांकि रोजमर्रा के खर्च को लेकर लोग अधिक सतर्क हो गए हैं लेकिन यात्रा एवं अर्थपूर्ण अनुभव उपभोक्ताओं की प्राथमिकता में बने हुए हैं। सर्वे के मुताबिक, लोग अब भावनात्मक संतुष्टि, व्यक्तिगत विकास और तनाव से राहत देने वाले अनुभवों पर कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं।

जनवरी 2026 में हुए अध्ययन के पहले चरण में महंगाई और आय स्थिरता को लेकर चिंता उभरनी शुरू हुई थी लेकिन अब इन चिंताओं में और वृद्धि देखी गई है। सर्वे के अनुसार, 2026 में अर्थव्यवस्था के बेहतर होने की उम्मीद 48 प्रतिशत लोगों को है जबकि जनवरी में यह आंकड़ा 60 प्रतिशत था।

मोदी और रोड्रिगेज के बीच वार्ता में भारत, वेनेजुएला ने दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी का संकल्प लिया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेलसी रोड्रिगेज के साथ व्यापक वार्ता की, जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों, फार्मास्यूटिकल, कृषि और ऑटोमोबाइल सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में दोनों देशों ने अपनी जरूरतों पर आधारित दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी स्थापित करने का संकल्प भी

लिया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच भारत की ओर से अप्रैल से वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद में तेजी आई है। यही नहीं, वेनेजुएला भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बनकर भी उभरा है। विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि बैठक में रोड्रिगेज का स्पष्ट संदेश था कि उनका देश भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार और इस तथ्य के मद्देनजर भारत को पसंदीदा ऊर्जा भागीदार के रूप में देखता है कि वह आने वाले कई वर्षों तक ऊर्जा बाजार में एक स्थिर खरीदार बना रहेगा। टंडन ने बताया कि जवाब में



प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऊर्जा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है और इसमें 'अपस्ट्रीम' (खोज और उत्पादन) और 'डाउनस्ट्रीम'

(शोधन और वितरण) दोनों गतिविधियां शामिल होंगी। उन्होंने कहा, वार्ता में मुख्य रूप से ऊर्जा साझेदारी स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया

गया। वे (वेनेजुएला) भारत को आने वाले कई वर्षों तक एक स्थिर और भरोसेमंद खरीदार के रूप में देखते हैं। इसलिए, भारत और वेनेजुएला के लिए ऊर्जा क्षेत्र में, मिलकर काम करने की पूरी संभावना एवं अनुकूलता है। उन्होंने बताया कि वार्ता में भारतीय पक्ष ने वेनेजुएला पर ओपेनजीसी विदेश के 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक के लाभों का मुद्दा भी उठाया। टंडन ने एक सवाल के जवाब में कहा, यह हमारा पैसा है। वे (वेनेजुएला) इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर हैं। उन्होंने बताया कि मोदी-रोड्रिगेज की वार्ता में सप्त्र

द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी का अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार करने के मुद्दे पर विचार-विमर्श हुआ। टंडन ने कहा, वेनेजुएला संसाधनों से समृद्ध देश है। वहां केवल खनिज ही नहीं, बल्कि सोना, हीरे और अन्य धातु भी पाए जाते हैं। इसलिए, खनिजों की अपार संभावनाएं हैं। वास्तव में इस बात पर चर्चा हुई कि उनके पास मौजूद संभावित भंडारों का आकलन कैसे किया जाए या क्या हम इस क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। उन्होंने इस सवाल का सीधा जवाब देने से परहेज किया कि क्या जनवरी में अमेरिकी सेना की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में

लिए जाने के बाद वेनेजुएला में हुए सत्ता परिवर्तन पर बैठक में चर्चा हुई। टंडन ने कहा, हम सब जानते हैं कि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन हुआ था। हम एक ऐसी सरकार के साथ काम कर रहे हैं, जो दोस्ताना रुख रखती है और भारत के साथ साझेदारी चाहती है। हम भी वैसा ही सहयोग देना चाहते हैं। और यह मत भूलिए कि वेनेजुएला पारंपरिक रूप से द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हमारा घनिष्ठ मित्र रहा है। उन्होंने बताया कि वार्ता में ब्रिक्स पर भी चर्चा हुई, जिसमें वेनेजुएला ने समूह की अध्यक्षता के लिए भारत और प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की।

दिसंबर तक 75 लाख घरों की छतों पर लग जाएंगी सौर प्रणाली : जोशी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बृहस्पतिवार को विश्वास जताया कि 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत दिसंबर तक 75 लाख घरों में छतों पर सौर इकाई (रूफटॉप सोलर) लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। फिलहाल इस योजना के तहत करीब 41 लाख घरों में सौर संयंत्र लगाए जा चुके हैं।

सरकार ने फरवरी, 2024 में इस योजना की शुरुआत 75,021 करोड़ रूपरे के आवंटन के साथ की थी। इसका उद्देश्य एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। योजना के तहत दो किलोवाट तक की सौर प्रणाली पर 60 प्रतिशत और दो से तीन किलोवाट के बीच की क्षमता पर अतिरिक्त 40 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जाती है। अधिकतम तीन किलोवाट तक सब्सिडी का



लाभ मिलता है। जोशी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, यह योजना देश के ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से बदलाव ला रही है और दो वर्षों में 40 लाख से अधिक परिवार इससे जुड़ चुके हैं। वहीं 65 लाख से अधिक आवेदन प्रक्रिया में हैं और अगले सात महीनों में 75 लाख घरों का लक्ष्य पाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से कम और मध्यम आय वाले परिवारों को इस

योजना का अधिक लाभ मिलेगा।

इससे पहले जोशी ने विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर लगाए जाने की प्रगति की समीक्षा की गई। जोशी ने कहा कि सरकारी भवनों पर सौर इकाई लगाने का 80 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है और अब तक 53,874 भवनों में कुल 855 मेगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि योजना शुरू होने से पहले जहां हर महीने करीब 7,000 रूफटॉप सोलर लगाए जाते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर तीन लाख से अधिक हो गई है। इसके साथ, मई 2026 में रिकॉर्ड 3.16 लाख सौर प्रणाली लगाई गई। इस योजना को अपनाने के बाद 17 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल स्यूच हो गया है, जबकि उपभोक्ताओं ने अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को बेचकर 421 करोड़ रूपरे से अधिक की आय अर्जित की है। योजना के तहत अब तक 22,750 करोड़ रूपरे से अधिक की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है, जिसमें अकेले 2,743 करोड़ रूपरे मई 2026 में दिए गए।

सीजेपी को 'अर्बन नक्सलियों' का समर्थन प्राप्त है: एन. रामचंद्र राव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) जैसे समूहों को अर्बन नक्सलियों और आम आदमी पार्टी (आप) जैसे संगठनों का समर्थन प्राप्त है।

राव ने जोर देकर कहा कि 'जेन जेड' भारतीय मूल्यों से पहचान रखती है और देश के युवा उन लोगों के झंडों में नहीं आएं, जिन्हें कथित तौर पर अंतरराष्ट्रीय निवेशक और पर्योपकारी जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त है। राव ने यह बयान तेलंगाना गठन दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब हैदराबाद द्वारा आयोजित 'मीट द प्रेस' कार्यक्रम में दिया। उन्होंने कहा, युवाओं को मुझे पर लड़ने का अधिकार है। कई छात्र संगठन हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि हर छात्र को भाजपा या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का ही अनुसरण करना चाहिए। 'कॉकरोच जनता पार्टी' कोई नई घटना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसे आम आदमी पार्टी जैसे दलों से जुड़े लोगों ने बनाया है। उन्होंने कहा कि वे लोग सोशल मीडिया के जरिए किसी तरह की खास विचारधारा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।



उनके अनुसार इनकी मौजूदगी केवल सोशल मीडिया तक सीमित है और जमीनी स्तर पर इनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सुर्यकांत द्वारा वकीलों को वरिष्ठ का दर्जा दिए जाने से संबंधित एक सुनवाई के दौरान कॉकरोच और परजीवी को लेकर की गई कथित टिप्पणियों से उपजे विवाद के बाद सोशल मीडिया पर सीजेपी ने लोगों के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सीजेआई ने बाद में स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणियां फर्जी और जाली डिग्रियों के माध्यम से कानूनी पेशे में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर केंद्रित थीं, जिन्हें गलत तरीके से पेश किया गया। यह मंच बेरोजगारी, परीक्षा-पेपर लीक और शिक्षा जैसे मुद्दों को उठाने के लिए मीन्स और तीखी राजनीतिक टिप्पणियों का उपयोग कर रहा है। हैदराबाद के तीन नगर निगमों के आगामी चुनावों के लिए भाजपा द्वारा अकेले चुनाव लड़ने या गठबंधन करने के सवाल पर राव ने कहा कि इस संबंध में अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा, "जहां तक हमारे वर्तमान रुख का सवाल है, हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि, अपनी जीत के लिए हमें सभी लोगों के समर्थन की आवश्यकता है। गठबंधन और अन्य मामलों पर निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा।"

प्रारंभिक परीक्षा में चेहरा मिलान प्रोटोकॉल सफलतापूर्वक लागू किया गया : यूपीएसएसी

नई दिल्ली/भाषा। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने हाल में संपन्न सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 में चेहरा मिलान प्रोटोकॉल सफलतापूर्वक लागू किया। यूपीएससी की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान में कहा है कि चेहरा मिलान प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी ने जो तस्वीर अपलोड की थी, वह परीक्षा देने के लिए एडमिट कार्ड के साथ पहुंचे व्यक्ति से मेल खाए। चेहरा मिलान प्रोटोकॉल ने परीक्षा केंद्रों पर मौजूद पर्यवेक्षकों को नोबाइल फोन आधारित सत्यापन के जरिये अभ्यर्थियों का वास्तविक समय में लाइव प्रमाणीकरण करने में सक्षम बनाया, जिससे निर्बाध पहचान पुष्टि सुनिश्चित हुई और अभ्यर्थियों के स्थान पर किसी और के परीक्षा देने की गुंजाइश समाप्त हो गई।

बयान के मुताबिक, यूपीएससी ने 24 मई को आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 के दौरान ने देशभर के सभी 2,072 परीक्षा केंद्रों पर वास्तविक समय में चेहरा मिलान प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। आंकड़ों के अनुसार, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 के लिए कुल 8,19,732 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से लगभग 5.49 लाख (67%) परीक्षा में शामिल हुए। बयान में कहा गया है कि यूपीएससी ने अपना चेहरा मिलान एप्लीकेशन डेवलपमेंट एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईडीडी) के तकनीकी सहयोग से विकसित और कार्यान्वित किया है। यूपीएससी ने एक ऐसी व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत किसी भी अभ्यर्थी को चेहरे के मिलान की प्रक्रिया से सफलतापूर्वक गुजरने के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

'माझे घर' योजना प्रवासी नहीं, गोवा के मूल निवासियों के लिए है : प्रमोद सावंत



पणजी/भाषा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार की 'माझे घर' योजना को लेकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसका उद्देश्य 'प्रवासियों' के मकानों को नियमित करना है, जबकि यह पहल केवल 'गोवा के मूल वासियों' के घरों को नियमित करने के लिए शुरू की गई है।

सावंत ने मडगांव में आयोजित एक कार्यक्रम में इस योजना के तहत स्वाभिम प्रमाणपत्र वितरित करने के दौरान कहा कि यह योजना केवल गोवा के मूल वासियों के पुश्तैनी घरों को नियमित बनाने के लिए है। उन्होंने कहा, "अब भी भ्रम फैलाया जा रहा है। कल एक पत्रकार ने मुझसे पूछा था कि क्या यह योजना प्रवासियों के मकानों को नियमित करने के लिए है? यह योजना वर्ष 1972 से पहले बसे पुश्तैनी घरों को नियमित करती है। ये मूल गोवा वासी हैं, जो लंबे समय से गोवा में रह रहे हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों को अपने घर खोने का डर सता रहा था क्योंकि दस्तावेजी खामियों के कारण उनका घर 'अनियमित' था, 'अवैध नहीं'। उन्होंने कहा, "कुछ लोग अपनी ही जमीन पर बने घरों के ध्वस्तीकरण की आशंका से भयभीत थे। यह योजना उन्हें उस डर से राहत प्रदान करती है।"



अहमदाबाद में दूषित जल: सात लोग अस्पताल में भर्ती

केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने स्थिति की समीक्षा की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अहमदाबाद/भाषा। अहमदाबाद शहर के घाटलोडिया इलाके में दूषित पानी के सेवन से कम से कम 50 लोग बीमार पड़ गए और उनमें से सात फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। नगर निगम ने सर्वेक्षण करने और धिक्किसा दल तैनात करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के अधिकारियों से बात की और स्थिति का जायजा लिया। इस घटना से इलाके में अतिशय और उल्टी के प्रकोपी की खबरों ने दहशत का कारण बना दिया। शाह ने कहा कि पाइपलाइन की मरम्मत के लिए युद्धस्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम उन सभी हाउसिंग सोसाइटी में पहुंची जहां अतिशय और उल्टी के मामले सामने आए थे और घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया, साथ ही पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोतियां भी वितरित की गईं।

आंध्र प्रदेश के इतिहास में चार जून सदा याद किया जाएगा : मुख्यमंत्री नायडू

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अमरावती/भाषा। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि चार जून आंध्र प्रदेश के इतिहास में एक यादगार मील का पत्थर है। उन्होंने याद दिलाया कि 2024 में इसी दिन मतदाताओं ने तेदेपा-भाजपा-जन सेना गठबंधन को निर्वाचक जनादेश दिया, जिससे राज्य को "विनाश से विकास की ओर" ले जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

तेलुगु देशम पार्टी, जन सेना और भाजपा के गठबंधन ने आंध्र प्रदेश विधानसभा में 164 सीटें जीतीं जबकि 2024 के चुनावों में वार्ड्सएसआर कांग्रेस केवल 11 सीटों तक सिमट गई। इन चुनावों



के बाद नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। नायडू ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "चार जून, 2024 आंध्र प्रदेश के इतिहास में एक ऐसा दिन है जो सदा याद किया जाएगा। आज उस ऐतिहासिक दिन के दो साल पूरे हो गए हैं जब जनता ने राज्य को विनाश से विकास की ओर ले जाने का अभूतपूर्व फैसला सुनाया था।" उन्होंने कहा, "यह जीत हमारे लिए केवल सत्ता नहीं है, बल्कि यह जनता द्वारा हमें सौंपी गई एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके तहत हमें राज्य का पुनर्निर्माण करना है।" तेदेपा प्रमुख नायडू ने कहा कि सरकार लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर काम कर रही है, जिसमें कल्याण, विकास और सुशासन उसके लक्ष्य हैं।

राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सतीश पूनिया और अल्का गुर्जर को बनाया उम्मीदवार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जायपुर/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीट पर होने वाले चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को सतीश पूनिया और अल्का गुर्जर को अपना उम्मीदवार घोषित किया।

पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी पूनिया भाजपा की राजस्थान इकाई के पूर्व अध्यक्ष हैं। जबकि गुर्जर पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हैं। राजस्थान की तीन राज्यसभा सीट के लिए चुनाव 18 जून को होंगे और परिणाम भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे। ये रिक्रिया इसलिए उत्पन्न

हुई हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, विधानसभा में वर्तमान शक्ति संतुलन के आधार पर भाजपा दो सीट जीतने की स्थिति में है। पूनिया और गुर्जर की उम्मीदवारी को भविष्य के राजनीतिक मुकामलों से पटवले जाट और गुर्जर समुदायों तक पहुंच बनाने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। दोनों नेता पार्टी में विभिन्न संगठनात्मक पदों पर रहे हैं और कई वर्षों तक राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे।



डॉ. सतीश पूनिया राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से भूगोल में पीएचडी की है। उनका राजनीतिक करियर छात्र राजनीति से शुरू हुआ, जब वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। इसके बाद वह भाजपा में विभिन्न पदों पर रहे, जिनमें प्रदेश भाजपा के महासचिव और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। उनका परिवार भी राजनीतिक रूप से सक्रिय है, चुने गए और 2019 में राजस्थान भाजपा अध्यक्ष बने। उन्होंने अन्य

राज्यों में भी संगठनात्मक जिम्मेदारियां संभालीं, जिनमें हरियाणा प्रभारी का पद शामिल है। वह एक राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार से आते हैं। उनके पिता पंचायत समिति प्रमुख रहे हैं। अल्का गुर्जर भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं। वह डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने पार्टी में कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक पदों पर कार्य किया है, जिनमें प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्टी प्रवक्ता शामिल हैं। वह 2013 में राजस्थान के बांदीकुई से विधायक चुनी गईं। वह राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रही हैं। उनका परिवार भी राजनीतिक रूप से सक्रिय है, उनके पति नाथू सिंह गुर्जर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मंत्री रहे हैं।



कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और उप-मुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने गुरुवार को बेंगलूर के विधान सभा में अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।

कर्नाटक में जन शिकायतों के निवारण के लिए अलग सचिवालय स्थापित किया जाएगा : डीके शिवकुमार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

बेंगलूर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार जनता की शिकायतों के निवारण के लिए एक अलग सचिवालय स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपने-अपने विभागों के लिए 15 दिनों के भीतर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही, उन्हें दबाव में न आने और ईमानदारी, विवेक और सकारात्मक

दृष्टिकोण के साथ काम करने का निर्देश दिया। पदभार ग्रहण करने के एक दिन बाद, मुख्यमंत्री शिवकुमार ने राज्य के शीर्ष नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। शिवकुमार ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, जनता की शिकायतों के निवारण के लिए एक अलग सचिवालय स्थापित किया जाएगा और राज्य भर से बेंगलूर आने वाले लोगों, जिनमें विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करने वाले भी शामिल हैं, की शिकायतों, मांगों या मुद्दों को सुनने के लिए एक मंत्री

नियुक्त किया जाएगा। ऐसे अलग सचिवालय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "हर दिन दो या तीन समूह यहां विरोध प्रदर्शन करने आते हैं। किसी को उनसे मिलना होगा और उनकी समस्याओं को समझना होगा। यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि उनकी मांगें वैध हैं या अवैध। अधिकारियों को उनसे मिलना चाहिए, तथ्यों को सुनना चाहिए और उनके मुद्दों को समझना चाहिए। इसलिए, एक अलग सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।"

बैठक में उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर, मंत्री रामलिंगा रेड्डी, मुख्य सचिव शालिनी रजनीश, पुलिस महानिदेशक एम ए सलीम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। शिवकुमार ने कहा कि नयी सरकार ने आज से अपना काम शुरू कर दिया है और अधिकारियों को सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में सूचित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जाति या धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के प्रभाव को बर्दाश्त नहीं करेगी और उन्होंने अधिकारियों से दबाव के आगे न झुकने का आग्रह किया।

मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कर्नाटक में समुदाय के पांच नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की

हबल्ली। कर्नाटक में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यह दावा करते हुए राज्य मंत्रिमंडल में समुदाय के पांच सदस्यों को शामिल करने की मांग की कि कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन से सत्ता में आई थी। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो पार्टी को अपने विधानसभा चुनाव में गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। यह मांग बुधवार शाम को बेलिगर स्थित हजरत सैयद फतेह शाह वाली दरगाह में मुस्लिम धर्मगुरुओं की एक सभा में उठाई गई। बैठक के दौरान बी जेड जमीर अहमद खान, एन ए हारिद, तनवीर सैत और सलीम अहमद समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग उठाई गई। एक धर्मगुरु ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "आम पांच मुसलमानों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई, तो आने वाले दिनों में आपको (कांग्रेस) गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।"

'दपरे' रेलवे सुरक्षा बल का बड़ा अभियान 49 बच्चों को बचाया, 1 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति जब्त

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

हबल्ली। दक्षिण पश्चिमी रेलवे (दपरे) के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने मई 2026 के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे संपत्ति की रक्षा के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। इस कार्यवाई के तहत आरपीएफ ने 100 लाख (1 करोड़) से अधिक की संपत्ति और प्रतिबंधित सामान बरामद किया है। ऑपरेशन 'नन्हें फरिश्ते' : पर से बिल्कुल 49 बच्चों (37 लड़के और 12 लड़कियाँ) को रेस्क्यू कर सुरक्षित उनके परिवारों या एनजीओ को सौंपा गया। यात्रियों के सामान की रिकवरी : मुस्तैदी दिखाते हुए यात्रियों के छूटे हुए 50.34 लाख कीमत के कीमती सामान (लेपटॉप, मोबाइल, गडने) को सुरक्षित मालिकों तक पहुंचाया गया। नशीले पदार्थ और अवैध शराब जब्त : 'ऑपरेशन



नार्कों' और 'सतर्क' के तहत 33.80 लाख का गांजा, 30 लाख की विदेशी सिगरेट और 83.31 लाख मूल्य की अवैध शराब जब्त की गई। दलालों पर नकेल (ऑपरेशन उपलब्ध) : टिकटों की कालाबाजारी करने वाले 37 दलालों को गिरफ्तार कर 6.19 लाख के रेलवे टिकट बरामद किए गए। महिला सुरक्षा (मेरी सहेली) : अकेले सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए 32 ट्रेनों में रिपल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। दपरे के महाप्रबंधक पी. अनंत ने आरपीएफ कर्मियों की इस चौबीसों घंटे की जांबाजी और उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन की सराहना की है। जिन्होंने अथक परिश्रम करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, और साथ ही प्रत्येक यात्री की भलाई की रक्षा करने की साझा जिम्मेदारी को भी दोहराया।

सत्ता के लिए शिवकुमार के पास जाओ; कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मेरे पास आओ : हरिप्रसाद

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

बेंगलूर। कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के नवनियुक्त अध्यक्ष बी के हरिप्रसाद ने बृहस्पतिवार को पार्टी नेताओं से कहा कि जो लोग सत्ता और पद चाहते हैं वे मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के पास जा सकते हैं और जो लोग संगठन को मजबूत करना चाहते हैं वे उनके पास आ सकते हैं। हरिप्रसाद ने कहा कि उनकी टिप्पणी का कोई अलग मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए और इसका अभिप्राय संगठन और सरकार दोनों की जिम्मेदारियों को साझा करते हुए आगे बढ़ना है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता हरिप्रसाद (71) को पार्टी की कर्नाटक इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरिप्रसाद ने डीके शिवकुमार की जगह ली है, जो बुधवार को ही राज्य के नए मुख्यमंत्री बने।

मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी यादव हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें उन्हें ताकत देनी होगी, इसके लिए हमें भी सड़कों पर उतरकर संघर्ष करना चाहिए।" उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, "सत्ता और पद चाहने वाले डी.के. शिवकुमार के साथ जाएं। जो कांग्रेस पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहते हैं तथा सोनिया गांधी और खरगे के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, वे सब मेरे साथ आएं। मैं यही कहना चाहता हूँ मेरी बातों का कोई अलग मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। मेरा कहना है कि संगठन और सरकार की जिम्मेदारियों को साझा करके आगे बढ़ना चाहिए।" उन्होंने कहा कि वह पार्टी को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह आश्वासन भी दिया कि वह उनके साथ हैं।



अपनी नियुक्ति पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि छात्र जीवन से ही उन्हें ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम करने का अनुभव है और यह अनुभव कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात के बाद वह आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे। हरिप्रसाद ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी मंत्री बनने की इच्छा नहीं जताई। उन्होंने कहा, "मैं सत्ता के लिए यहां नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही और कार्यकर्ता हूँ, जो इसकी कार्यकारिणा, सिद्धांतों और संविधान का पालन करता है... मैंने 20 राज्यों में विभिन्न स्तरों पर 53 वर्षों तक पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी के लिए काम करना और इस देश को जानना मेरा जूनून है।" उन्होंने कहा कि शिवकुमार अब

मुख्यमंत्री और जी परमेश्वर उपमुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग मिलकर राज्य को आगे ले जाएंगे। हरिप्रसाद ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर एसआईआर और सीएए की प्रक्रिया के माध्यम से वास्तविक मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाए जाने के खिलाफ संघर्ष करना है। उन्होंने कहा, भारत की अवधारणा की रक्षा के लिए हमें सभी धर्मों, जातियों और भाषाओं को साथ लेकर चलना होगा। हमें सत्ता या पद के लिए नहीं, बल्कि इसके खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ लड़ना होगा। कांग्रेस पार्टी जिन विचारधारा और सिद्धांतों में विश्वास रखती है, इन्हें आगे बढ़ाना होगा। "हरिप्रसाद ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कर्नाटक में इन दोनों से लड़ना होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस 2028 में राज्य में सत्ता में वापस आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस 2023 में जनता से किए गए वादों को पूरा किया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना है।

राजेश एक्सपोर्ट्स में एलआईसी की हिस्सेदारी का होना चिंताजनक : कांग्रेस

चेन्नई/नई दिल्ली। कांग्रेस ने राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड नामक कंपनी से जुड़ी कथित अनियमितता का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि इस कंपनी में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की हिस्सेदारी का होना चिंताजनक है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने साया भी किया कि क्या एलआईसी द्वारा इतनी बड़ी हिस्सेदारी का अधिग्रहण सरकारी तंत्र के निर्देशों के तहत किया गया था? भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के प्रवर्तक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राजेश मेहता पर कंपनी की प्रतिभूतियों में लेन-देन करने की रोक लगा दी। उन पर वित्तीय विवरण में बड़े पैमाने पर भ्रामक जानकारी देने और धन के गबन का आरोप लगाया गया है।



मोबाइल आरपीएफ कार्यालय का हुआ उद्घाटन

बेंगलूर/दक्षिण भारत। यहां दक्षिण पश्चिमी रेलवे के बेंगलूर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक आशुतोष कुमार सिंह ने आज केएसआर बेंगलूर स्टेशन पर एक नए पोर्टेबल (मोबाइल) आरपीएफ कार्यालय का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन जमीनी स्तर पर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और रेलवे सुरक्षा बल की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के तहत, बेंगलूर मंडल में रणनीतिक आरपीएफ चौकियों पर सात पोर्टेबल आरपीएफ कार्यालय इकाइयां खरीदी और स्थापित की गई हैं। इन इकाइयों को रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगे आरपीएफ कर्मियों को लचीला, कुशल और त्वरित-तैनाती वाला बुनियादी ढांचागत सदस्योपकरण बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, विशेष रूप से रास्ते में पड़ने वाले और संवेदनशील रेलवे स्टेशनों पर।

मानक आरपीएफ चौकियों के समान सुविधाओं से सुसज्जित, ये कंटेनर-आधारित इकाइयां परिचालन आवश्यकताओं और अनुरूप अनुकूलित की जा सकती हैं। पोर्टेबल आरपीएफ कार्यालयों के रूप में कार्य करने के अलावा, ये आपात स्थितियों, विशेष सुरक्षा व्यवस्थाओं और आपदा प्रतिक्रिया स्थितियों के दौरान तैनात कर्मियों के लिए अस्थायी आवास, कमांड और कंट्रोल सेंटर, फिल्टरिंग सहायता सुविधाएं और परिचालन केंद्र के रूप में भी काम कर सकती हैं। ये पोर्टेबल कार्यालय पूरे मंडल में

जमीनी और ट्रेन एरकाउंट च्युटी करने वाले आरपीएफ कर्मियों के लिए लाभदायक और पारामुन सुविधाओं के रूप में भी कार्य करेंगे। इस अवसर पर बोलते हुए, आशुतोष कुमार सिंह ने बेंगलूर मंडल में सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नवीन समाधान अपनाने में रेलवे सुरक्षा बल के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर बेंगलूर मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त डॉ. श्रेयंस चिंत्ताकर, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और आरपीएफ कर्मियों के साथ उपस्थित थे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला-संचालित मूंगफली प्रसंस्करण इकाई का किया उद्घाटन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

यादगीर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यादगीर जिले में महिलाओं के नेतृत्व में संचालित नाबाई समर्थित मूंगफली प्रसंस्करण इकाई का बृहस्पतिवार उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जिला हर वर्ष लगभग 22,500 टन मूंगफली का उत्पादन करता है और इसमें मूल्य संवर्धन की काफी संभावना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हमने अब एक ऐसी इकाई स्थापित की है जो मूंगफली को भूख सकती है, तेल निकाल सकती है और पीनट बटर जैसे उत्पाद बना सकती है।"



उन्होंने पेड्डापल्ली महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड की सराहना की, जो इस इकाई का संचालन कर रही है। मंत्री ने कहा कि कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में स्थापित ऐसी सात मूल्य संवर्धन इकाइयों में से यादगीर की इकाई अकेली है जिसे पूरी तरह महिलाएं चला रही हैं। सीतारमण ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि इस इकाई का संचालन करने वाली सरकारें ही नहीं बल्कि लोगों तथा स्थानीय प्रशासन को भी अधिक प्रयास करने होंगे। वित्त मंत्री ने इकाई में बने उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच की भी मांग की और नाबाई से उत्पादक कंपनी को ई-कॉमर्स एवं क्रिक-कॉमर्स मंच के माध्यम से विस्तार में मदद करने का अनुरोध किया। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध आम उत्पादक जिले से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि "चित्तूर अपने आमों के लिए प्रसिद्ध है। मुझे उम्मीद है कि यादगीर अपनी मूंगफली के लिए प्रसिद्ध होगा।" उन्होंने कहा कि नाबाई समर्थित इस इकाई के सफल संचालन से

जिले में निजी निवेश को भी बढ़ावा मिल सकता है। जिले के लिए निरंतर समर्थन का आश्वासन देते हुए सीतारमण ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अभी काफी काम किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि यादगीर में महिला साक्षरता दर बहुत कम है, बहुआयामी गरीबी अधिक है और प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है जो चिंता का विषय है। मंत्री ने कहा कि यादगीर को केंद्र, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से तुरंत और विशेष ध्यान की आवश्यकता है। सीतारमण ने कहा कि यादगीर और पड़ोसी रायचूर को "आकांक्षी जिला" नामित किया गया है क्योंकि विकास के लाभ यहां अन्य क्षेत्रों की तुलना में समान रूप से नहीं पहुंचे हैं तथा सभी स्तरों की सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, "कर्नाटक के मानव विकास सूचकांक में यादगीर कहां है? यह देखकर मुझे दुःख होता है। यह पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे स्थान पर

नहीं है। यह सबसे नीचे है। यादगीर कर्नाटक में अंतिम स्थान पर है।" यह गहरी पीड़ा के साथ कह रही हैं।" उन्होंने कहा कि यादगीर के लोगों की कोई गलती नहीं है और जिले की वर्तमान स्थिति इसलिए है क्योंकि विकास वर्षों तक वहां ठीक से नहीं पहुंच सका। सीतारमण ने कहा कि देश भर में लड़कियां इंजीनियर, सिविल सेवक और वरिष्ठ कॉर्पोरेट अधिकारी बन रही हैं, लेकिन यादगीर काफी पीछे है। उन्होंने बताया कि यहां हर 100 में से केवल 41 महिलाएं ही साक्षर हैं या स्कूल/काॅलेज जा रही हैं। बुनियादी ढांचे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल हैं, लेकिन शिक्षक नहीं हैं, शौचालय नहीं हैं और कक्षाएं भी पर्याप्त नहीं हैं।

वित्त मंत्री ने जिले में गरीबी संकेतकों का भी उल्लेख किया और कहा कि देश में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। फिर भी यादगीर अब भी सबसे अधिक प्रभावित जिलों में है। उन्होंने कहा कि बेंगलूर की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है जबकि यादगीर सबसे निचले स्तर पर है। सीतारमण ने कहा कि यादगीर की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और लगभग 75 प्रतिशत भूमि खेती के अंतर्गत है। उन्होंने बादेयली गांव में किसानों के प्रशिक्षण और साझा सुविधा केंद्र का भी उद्घाटन किया। सीतारमण के कार्यालय ने सोशल मीडिया चैनल 'एक्स' पर लिखा, "वित्त मंत्री द्वारा नाबाई के सहयोग से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीएलई) योजना के तहत स्थापित, यादगीर में किसानों का प्रशिक्षण एवं साझा सुविधा केंद्र (सीएफसी) मूंगफली को उच्च मांग वाले कई मूल्य-वर्धित उत्पादों में प्रसंस्करण के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है।"

Table with 2 columns: प्रकाशित (31/03/2026) and प्रतिस्थापित (31/03/2026). Includes details for the 30.05.2026 election and candidates.

Table with 4 columns: क्रम सं., विवरण, प्रकाशित, प्रतिस्थापित. Lists candidates and their vote counts for various constituencies.

Table with 2 columns: विवरण, प्रकाशित, प्रतिस्थापित. Lists candidates and their vote counts for various constituencies.

विवरण, प्रकाशित, प्रतिस्थापित. Lists candidates and their vote counts for various constituencies. Includes details for the 30.05.2026 election and candidates.



संबल सखी और माय भारत वॉलंटियर्स सरकार और आमजन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी : भजनलाल शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-विकसित राजस्थान के विजन को साकार करने के लिए राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की युवा और महिला शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। युवा और महिलाएं जनकल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने तथा सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय भागीदारी निभाएं और प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाएं।

मुख्यमंत्री बुधवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर संबल सखी एवं माय भारत वॉलंटियर्स से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा, महिला, किसान, गरीब के उत्थान, कल्याण और समान के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे राज्य सरकार और आमजन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी बनें, जिससे विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, डिजिटल सेवाओं, ई-गवर्नेंस, डिजिटल भूगतान और तकनीक आधारित सुविधाओं की जानकारी जरूरतमंदों तक पहुंचे और उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान से देश में लिंगानुपात में सुधार हुआ, घर-घर शौचालय निर्माण से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की सुनिश्चिता हुई। वहीं, उच्चला योजना के जरिए धुएँ से मुक्ति मिली और जन-धन खातों के खुलने से जरूरतमंदों तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए महिलाओं के हाथ में घर की चाबी सौंपी गई। वहीं, आधी आबादी को उसका हक देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य में बेटीयों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाने के साथ ही प्रोत्साहन के रूप में स्कूटी दे रही है। इसके लिए अब सीधे उनके खातों में रुपये जमा करने का प्रावधान भी किया गया है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान के विकास के लिए सबसे पहले हमने जल उपलब्धता का रोडमैप बनाया, जिसके तहत राम जल सेतु लैंक परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना का विस्तार, आईजीएनपी एवं गंग नहर का सुदृढीकरण, माही बांध परियोजना, सोम-कमला-अम्बा परियोजना, ब्राह्मणी नदी परियोजना जैसे कार्य प्रगति पर हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को उर्जा के

क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इसी दिशा में हमने ढाई वर्ष में उर्जा उत्पादन को बढ़ाया है। वहीं, वर्ष 2027 तक प्रदेशभर में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य तय किया है तथा अब तक 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराया जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के क्रम में अब तक सवा लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। वहीं, प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देकर निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया, जिसमें हुए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 9 लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा रोजगार प्रदाता भी बनें। राजस्थान में कृषि पैदावार की विविधता के कारण प्रसंस्करण उद्योग में अपार संभावना है। इसी क्रम में युवा प्रोसेसिंग युनिट्स स्थापित कर अन्य लोगों को रोजगार दें और किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण में भी भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश में दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्यों में शामिल है। हमारी सरकार दूध संकलन केंद्रों की संख्या एवं दूध प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता में वृद्धि कर रही है। साथ ही, पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दे रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की 6 हजार रुपये की किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य सरकार भी 3 हजार रुपये की सम्मान निधि दे रही है। वहीं, किसानों को गैर एमएसपी पर 150 रुपये का बोनस दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांवों और शहरी वाडों के विकास का रोडमैप भी बना रही है। इसमें 'वोकल फॉर लोकल' के जरिये स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही, पंच गौरव के जरिए प्रत्येक जिले में एक खेल, एक वनस्पति, एक उपज, एक पर्यटन स्थल और एक उत्पाद को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत है, यहां की 4.5 प्रतिशत आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है। इसलिए युवा विकास, नवाचार, निवेश, रोजगार, शिक्षा और जनकल्याण के क्षेत्र में राजस्थान को देश में अग्रणी राज्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दें। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रतिभा, संस्कृति, पर्यटन, कृषि, उद्योग, शिक्षा और आध्यात्मिक विरासत के क्षेत्र में देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। प्रदेश के युवाओं ने देश और दुनिया में अपनी मेहनत, ईमानदारी और कार्यकुशलता का लोहा मनवाया है। राजस्थान की ऐतिहासिक दुर्ग, महल, वन्यजीव अभयारण्य, झीलें और धार्मिक स्थल इसे पर्यटन की दृष्टि से विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं।

मीलवाड़ा में महिला से यौन शोषण और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप, एक गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के मीलवाड़ा में पुलिस ने 35 वर्षीय एक महिला का यौन शोषण करने, उसे ब्लैकमेल करने, उसका जबरन धर्म परिवर्तन और आर्थिक शोषण करने के आरोपों में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया, महिला ने उससे पैसे वसूल एवं उसे ऋण लेने के लिए भी भजबू किया। पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने

दिलाने के बहाने उससे दोस्ती की और बाद में शहर के एक रिजॉर्ट में उसका यौन शोषण किया। महिला ने कहा कि आरोपी ने आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। पुलिस के अनुसार, शिकायत में यह भी आरोप है कि आरोपी उसे दिल्ली ले गया और जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसकी शादी कर दी। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी और उसके परिवार ने उससे पैसे वसूल एवं उसे ऋण लेने के लिए भी भजबू किया। पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने

बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया तथा जांच में शोषण और वित्तीय लेन-देन के सबूत मिले। राणा ने कहा, आरोपों की पुष्टि के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात जांच की जा रही है कि अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं या नहीं। उन्होंने बताया कि पुलिस धर्म परिवर्तन से जुड़े आरोपों और संभावित नेटवर्क की भी जांच कर रही है। उन्होंने कहा, वित्तीय लेन-देन और अन्य आरोपों की भूमिका समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।



प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना में प्रदेश के 8 शहरों में 1150 इलेक्ट्रिक बसों का होगा संचालन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना में प्रदेश के 8 शहरों में 1150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना है। इसके संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय संचालन समिति की द्वितीय बैठक मुख्य सचिव वी. श्रीनिवासा की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में योजना के तहत राज्य के पात्र शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, विभिन्न वित्तीय अनुमोदन तथा संबंधित विभागों के मध्य समन्वय से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में राज्य के विभिन्न शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के लिए डिग्री अथॉरिटी के विकास, चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना तथा 'बिहाइंड द मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर' के विकास संबंधी कार्यों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को योजना से जुड़े कार्य समन्वय रूप से पूर्ण करने तथा परियोजनाओं के

क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य के 8 शहरों को 1150 ईबस आवंटित हुई हैं। जयपुर में 450, जोधपुर और बीकानेर में 125125, अजमेर, अलवर और कोटा में 100100, उदयपुर सीकर और भीलवाड़ा में 5050 ईबस संचालित की जानी हैं। बसों का ट्रायल हो चुका है, चार्जिंग स्टेशन समेत अन्य सुविधाओं का विकास तेज गति से किया जा रहा है। समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत राजस्थान के आठ पात्र शहरों को प्राप्त होने वाली वित्तीय स्वीकृतियों एवं सहायता के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बस संचालन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शहरों में स्थित वर्तमान बस डिपो के नवीनीकरण एवं उन्नयन संबंधी प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई।

राज्य को 1150 ईबस आवंटित हुई हैं। जयपुर में 450, जोधपुर और बीकानेर में 125125, अजमेर, अलवर और कोटा में 100100, उदयपुर सीकर और

भीलवाड़ा में 5050 ईबस संचालित की जानी हैं। बैठक में परिवहन विभाग, वित्त विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, उर्जा विभाग तथा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) के वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को समन्वित प्रयासों के माध्यम से योजना का प्रभावी एवं समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ, हरित एवं टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ किया जा सके। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने कहा कि विभाग द्वारा योजना की प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाना है।

कमरे में फंदे से लटका मिला जेईई अभ्यर्थी का शव, आत्महत्या की आशंका

कोटा। राजस्थान के कोटा में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) की तैयारी कर रहे 17 वर्षीय छात्र का शव यहां राजीव गांधी नगर स्थित 'पेइंग गेट' (पीजी) में छत के पंखे से लटका मिला। पुलिस ने छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि छात्र द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम के पीछे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है। मृतक छात्र की पहचान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के रहने वाले आर्यन ओझा के रूप में हुई है। यह इस साल फरवरी से कोटा के एक कॉलेज संस्थान में जेईई की तैयारी कर रहा था और शहर के राजीव गांधी नगर में एक पीजी में रह रहा था। पुलिस के अनुसार, बुधवार रात करीब 10:45 बजे पीजी में रहने वाले अन्य छात्रों ने उसका शव देखा और पुलिस को सूचित किया।

पटवारी पांच हजार रुपये की रिश्तव लेते-रंगे हाथ गिरफ्तार

जयपुर। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की अलवर चोकी टीम ने बृहस्पतिवार को खैरथल-तिजारा जिले की सांथलका तहसील में कार्यरत एक पटवारी को पांच हजार रुपये की रिश्तव लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एसीबी के अनुसार गिरफ्तार पटवारी की पहचान आशा देवी के रूप में हुई है। एसीबी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, पटवारी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पिता के निधन के बाद स्वयं और अन्य परिजनों के नाम इंतकाल दर्ज कराने तथा राज्य स्टिकॉर्ड में उसके पिता का नाम सही करवाने के एवज में पटवारी 30 हजार रुपये की रिश्तव मांग रही थी और उसे परेशान कर रही थी। शिकायत के सत्यापन के दौरान एसीबी की टीम ने पाया कि आरोपी पटवारी परिवारों से 10 हजार रुपये की रिश्तव ले चुकी थी तथा पांच हजार रुपये और मांग रही थी। इसके बाद एसीबी टीम ने बृहस्पतिवार को जाल बिछाकर कार्रवाई की और पटवारी आशा देवी को पांच हजार रुपये की रिश्तव लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।

जयपुर में 82 वर्षीय महिला ने 14वीं मंजिल से कूदकर जान दी

जयपुर। जयपुर के हरमाड़ा क्षेत्र स्थित एक आवासीय सोसाइटी में 82 वर्षीय महिला ने 14वीं मंजिल से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना सनसिटी के जय विलास अपार्टमेंट में हुई, जहां लक्ष्मी जैन अपनी बेटी और दामाद के साथ रहती थीं। पुलिस ने बताया कि बुधवार को महिला के परिजन अजमेर गए हुए थे और लक्ष्मी की तबीयत ठीक नहीं होने व दृष्टि कमजोर के कारण वे फ्लैट को बाहर से बंद कर गए थे। प्राथमिक जांच के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह लक्ष्मी ने बालकनी से छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों ने उन्हें जमीन पर लहलुहान अवस्था में देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पूर्वी व पश्चिमी हिस्सों में बारिश और आंधी

जयपुर। राजस्थान के पूर्वी व पश्चिमी हिस्सों के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि इस दौरान थुलभरी आंधी और गरज के साथ तेज हवा भी चली। मौसम विभाग के अनुसार, फलोदी सहित पश्चिमी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर रात के समय गर्मी रही। विभाग ने बताया, कोटा जिले के सांगोद में सबसे अधिक 28 मिलीमीटर (मिमी) वर्षा हुई। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान जैसलमेर में 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सांगरिया (हनुमानगढ़) में 33.2 डिग्री सेल्सियस रही। अजमेर में न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

गहलोत ने अरावली के संबंध में उच्चस्तरीय समिति के गठन का स्वागत किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी रिपोर्ट की स्वतंत्र समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति का स्वागत किया है और उम्मीद जताई कि समिति के प्रयासों से छोटी पहाड़ियों का संरक्षण सुनिश्चित होगा व अरावली का प्राकृतिक सुरक्षा कवच मजबूत बना रहेगा।

गहलोत ने बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में कहा, "अरावली की परिभाषा और संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय द्वारा पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन स्वागतयोग्य कदम है। हमें उम्मीद है कि यह समिति अरावली के पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) को सुरक्षित रखने वाली एक वैज्ञानिक परिभाषा तैयार करेगी।"

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की रिपोर्ट में मौजूद मुद्दों और "महत्वपूर्ण अस्पष्टताओं" की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया है। अदालत ने समिति को उन बिंदुओं की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया है, जिन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। गहलोत ने कहा कि राजस्थान और देश जिस तरह भीषण गर्मी तथा मौसम संबंधी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उसे देखते हुए अरावली का संरक्षण व आने वाली पीढ़ियों का

भविष्य सुरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एक-दो दशक पहले तय किए गए मानदंड आज की बदलती और गंभीर परिवर्तन परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकते, ऐसे में समिति को वर्तमान परिवर्तनीय संकट को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। कांग्रेस नेता ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा, "केंद्र की नीतियों ने अरावली के अस्तित्व के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया था। इसके बाद 'अरावली बचाओ' अभियान को बल मिला। मुझे दूर विश्वास है कि समिति के प्रयासों से हमारी लघु पहाड़ियों का संरक्षण होगा और अरावली का यह प्राकृतिक सुरक्षा कवच मजबूत बना रहेगा।"

पर्यावरण संरक्षण जन-जन का दायित्व : देवनाली

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनाली ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर कहा है कि पर्यावरण संरक्षण जन-जन का दायित्व है। उन्होंने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिवस मनाने का विषय नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए सतत संकल्प और सामूहिक प्रयास का विषय है। स्पीकर देवनाली ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी जीवनशैली में पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार अपनाना होगा। उन्होंने नागरिकों से अधिकाधिक वृक्षारोपण करने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने, प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने तथा स्वच्छता और हरित विकास के प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भाव ही पर्यावरण संरक्षण की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नई गति मिलेगी। राजस्थान हरित व स्वच्छ प्रदेश के रूप में नई पहचान स्थापित करेगा।

जयपुर में छह मंजिला इमारत ढहाई गई, आसपास के मकान खाली कराए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। जयपुर के रामगंज क्षेत्र स्थित चीता वॉल का मोहल्ला में निर्माण के लिए छह मंजिला इमारत को नगर निगम ने बृहस्पतिवार को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई तकनीकी विशेषज्ञों की निगरानी में की गई ताकि आसपास की इमारतों को न्यूनतम जोखिम हो। उन्होंने बताया कि नौ मई को निर्माण कार्य के दौरान कुछ पिलर क्षतिग्रस्त हो जाने से इमारत एक ओर झुक गई थी। ध्वस्तीकरण से पहले प्रशासन ने क्षेत्र के सभी मार्ग सील कर दिए और अवरोधक लगाकर आम लोगों की आवाजाही रोक दी। कानून-

व्यवस्था बनाए रखने के लिए रामगंज थाना पुलिस को मौके पर तैनात किया गया। एहतियात के तौर पर आसपास के 10 से 15 मकानों को खाली कराया गया और वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। साथ ही क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। नगर निगम के किशनपोल जोन के उपायुक्त विजेंद्र सिंह ने बताया कि छह मंजिला यह इमारत बिना अनुमति के अवैध रूप से बनाई जा रही थी। उन्होंने बताया कि नौ मई को इसके एक हिस्से में दरार आ गई जिसके बाद उसी दिन इमारत को खाली करा लिया गया। सिंह ने बताया कि इसके बाद नगर निगम ने विशेषज्ञों की राय के आधार पर इमारत को सुरक्षित घोषित कर उसे ध्वस्त करने का निर्णय लिया।

जयपुर नगर निगम आयुक्त ने संपर्क हेल्पलाइन का किया निरीक्षण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। जयपुर नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की और

परिवादियों से फोन पर फीडबैक लिया। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों के त्वरित एवं समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए शिकायतों की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। कसेरा ने कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच से जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण में संपर्क हेल्पलाइन मील का पथर साबित हो रही है।

ग्रामीण पेयजल सेवाओं को और प्रभावी बनाने की पहल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

जयपुर/दक्षिण भारत। जिला कलक्टर जयपुर संदेश नायक के निदेशानुसार जिले में निर्धारित मानकों के आधार पर चयनित ग्रामों में जिला प्रशासन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), माननीय सांसद एवं माननीय विधायक तथा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों के संयुक्त दल द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों का गहन निरीक्षण किया जा रहा है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान पेयजल योजनाओं की प्रगति, घरेलू नल कनेक्शनों की स्थिति, जलापूर्ता तथा गुणवत्ता एवं नियमितता तथा आमजन को प्राप्त हो रहे लाभों का विस्तृत मूल्यांकन किया गया।

निरीक्षण दल द्वारा ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, सुझावों एवं अपेक्षाओं की जानकारी भी प्राप्त की गई। जिला कलक्टर ने बताया कि

इस अभियान के अंतर्गत जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के झोटावाड़ा, जोबनर, आमेर, गोविंदवाड़ा, सांभर, किशनगढ़-रेनवाल, फागी, सांगानेर, चाकसू, बरसी, जालसू, आंधी, जमवारामगढ़, मौजमाबाद, दूदू, कोटखावदा, तुंगा, मांधोराजपुरा एवं शाहपुरा ब्लॉकों की कुल 40 जल योजनाओं का निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से 03 जून 2026 तक कुल 23 जल योजनाओं का निरीक्षण पूर्ण किया जा चुका है, जबकि शेष 17 योजनाओं का निरीक्षण आगामी दिनों में किया जाएगा। संयुक्त निरीक्षण दल ने विभिन्न स्थलों का भ्रमण कर कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा की। जहां आवश्यक पाया गया, वहां सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। निरीक्षण के दौरान प्राप्त सुझावों

तथा फीडबैक स्तर पर चिन्हित कमियों के आधार पर एक डिस्ट्रिक्ट इम्प्रूवमेंट प्लान तैयार किया जाएगा, जिससे जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं को और अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं अधिकाधिक बनाया जा सके। जिला कलक्टर ने बताया कि इस प्रकार के निरीक्षण एवं समीक्षा अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेंगे तथा प्राप्त सुझावों एवं चिन्हित कमियों के आधार पर आवश्यक सुधारालमक कार्यों को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की उच्च प्राथमिकता है तथा जल जीवन मिशन के उद्देश्यों की प्रभावी प्राप्ति के लिए सतत मॉनिटरिंग एवं नियमित फॉलोअप सुनिश्चित किया जाएगा।

कसेरा ने हेल्पलाइन पर परिवादियों से संपर्क किया और उनकी समस्याओं को विस्तार और संवेदनशीलता से सुना। परिवादियों ने उन्हें टूटी सड़को के निर्माण/मरम्मत , जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में हुए नामों की गड़बड़ियों और पड़े जारी करने ,सफाई व्यवस्था आदि से सम्बंधित शिकायतों के बारे में बताया। आयुक्त ने परिवादियों कि समस्याओं पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सम्बंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के लिए निर्देशित किया।



जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अंतर-राज्यीय और वैश्विक सहयोग बढ़ाना जरूरी: माझी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पुरी/भाषा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर-राज्यीय और वैश्विक सहयोग बढ़ाने का बृहस्पतिवार को आह्वान किया। माझी पुरी में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह (डीआरआरजी) की तकनीकी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ाने, जलवायु अनुकूलन और सतत विकास के प्रति ओडिशा की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की

ओर से आयोजित तीन दिवसीय बैठक में ब्रिक्स समूह के 11 सदस्य देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। माझी ने बैठक को वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। उन्होंने कहा कि बैठक का विषय 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' है, जो अधिक सहयोग के जरिये जीवन, आजीविका और भावी पीढ़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तत्काल प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालता है। माझी ने कहा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण अब केवल क्षेत्रीय ष्टिता का विषय भर नहीं है, बल्कि सतत विकास, आर्थिक स्थिरता और मानव सुरक्षा सुनिश्चित करने की आधारशिला भी है।



रक्षा मंत्री ने संचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों की वित्तीय सीमा दोगुना की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को सैन्य संचालन दक्षता को मजबूत करने और अनुबंधों को शीघ्रता से पूरा करने के साथ-साथ परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 'फील्ड कमांडरों' की वित्तीय शक्तियों में दोगुना बढ़ाव देते हुए घोषणा की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि थलसेना, वायुसेना और नौसेना के कमांडरों को सीपी गैर विशेष वित्तीय शक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है तथा तत्काल संचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान की गई कुल सीमा में 100 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वित्तीय शक्तियों में वृद्धि के अलावा, सेना के तीनों अंगों की संयुक्त खरीद को बढ़ावा देने के लिए नये प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिसमें सामान्य खरीद की तुलना में अधिक अधिकार दिये गए हैं। मंत्रालय ने कहा, "वस्तुओं और सेवाओं की

खरीद को विकेंद्रीकृत करने के लिए कई नये सक्षम वित्तीय प्राधिकरणों की स्थापना की गई है।" रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में 'रक्षा सेवाओं के लिए वित्तीय शक्तियों के हस्तांतरण' संबंधी संशोधित नियमावली जारी की। मंत्रालय ने कहा, "वित्तीय शक्तियों में 100 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है, और कुछ मामलों में तो यह वृद्धि दोगुनी से भी अधिक है। इससे फील्ड कमांडरों की संचालन दक्षता और मजबूत होगी। इससे अनुबंधों को शीघ्रता से संपन्न करने तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।" मंत्रालय ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और अनुसंधान एवं विकास के लिए आवंटित वित्तीय शक्तियों को दोगुना कर दिया गया है ताकि विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं पर निर्भरता कम करके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, वित्तीय शक्तियों के संशोधित हस्तांतरण से चालू वर्ष के बजटिय आवंटन के अनुसार राजस्व बर्ण से 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीद में मदद मिलेगी।

बिहार : राबड़ी आवास विवाद को लेकर राजग सरकार पर बरसे तेज प्रताप



दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री और अपनी मां राबड़ी देवी के सरकारी आवास को बंद करने को आवंटित किए जाने के मुद्दे पर बृहस्पतिवार को बिहार सरकार पर निशाना साधा। जनशक्ति जिनता दल (जेजेडी) के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने यह भी मांग की कि राज्य की राजधानी में सरकारी बंगलों में रह रहे अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों

नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी को भी इसी तरह के नोटिस जारी किए जाएं। यादव ने 'पीटीआई-वीडियो' से बातचीत में कहा, "यदि राबड़ी देवी जी को 10, सकुलर रोड स्थित बंगला खाली करने के लिए राज्य सरकार ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो पटना में सरकारी बंगलों में रह रहे अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों नीतीश कुमार जी और जीतन राम मांझी जी को भी ऐसे ही नोटिस दिए जाने चाहिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उषेन्द्र कुशवाहा से भी मकान खाली करने को कहा जाना चाहिए, जो पटना में सरकारी बंगले में रह रहे हैं।" राबड़ी देवी जिस सरकारी बंगले में रह रही हैं, उसे खाली करने से उनके इनाकार के बाद विवाद खड़ा हो गया है। यह आवास अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है।

'पर्यटन को सांस्कृतिक पुनर्जागरण और रोजगार सृजन से जोड़कर आगे बढ़ाएं'

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को कहा कि पर्यटन विकास को केवल आधारभूत संरचना निर्माण तक सीमित न रखकर उसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण, स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और वैश्विक पहचान से जोड़ते हुए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को

नई गति देने में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास के माध्यम से स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, पारंपरिक कला, खानपान, संस्कृति और सेवा क्षेत्र को भी व्यापक अवसर प्राप्त होंगे। आदित्यनाथ ने कहा कि पर्यटन नीति ऐसी होनी चाहिए जो निवेश आकर्षित करे, रोजगार के अवसर बढ़ाए और पर्यटकों को विशिष्ट अनुभव प्रदान करे। उन्होंने पर्यटन नीति-2022 में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करते हुए



उत्तर प्रदेश को निवेश, नवाचार और अनुभव-आधारित पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण से जुड़े 'ज्ञान भारतमिशन' की समीक्षा करते हुए कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियां हमारी सभ्यता, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक चेतना की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि इनका संरक्षण और डिजिटलीकरण केवल अभिलेखीकरण का कार्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को

अपनी जड़ों से जोड़ने का भी माध्यम है। बयान के अनुसार, बैठक में नीम करोली बाबा सर्किट और बुदेलखंड फोटो सर्किट के रूप में नए पर्यटन क्षेत्रों के विकास पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने आगरा में निर्माणाधीन छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, लखनऊ में नव-लोकप्रिय 'नौसेना शौर्य वाटिका' और निर्माणाधीन आईएनएस गोमती शौर्य संग्रहालय, नैनिहारपुर के समग्र विकास, मिर्जापुर-विंध्याचल क्षेत्र के लिए तैयार किए जा रहे एकीकृत मास्टर प्लान तथा चित्रकूट स्थित प्राचीन सोमनाथ मंदिर के संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों की भी समीक्षा की।



मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में आग से पांच की मौत, मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने बताया शोक

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुजफ्फरपुर (बिहार)/भाषा। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के हपुरा थानाक्षेत्र में एक निजी अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में बृहस्पतिवार तड़के भीषण आग लगने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के शशांक कुमार, कृष्णचंद्र सिंह और गीता देवी, शिवहर जिले के उदय कुमार तथा सीतामढ़ी जिले की चंचला वर्मा के रूप में हुई है। नगर आयुक्त ऋतुराज सिंह ने कहा, "अब तक पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।" इससे पहले, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया था कि सुबह घटना की सूचना मिलने पर मृतकों की संख्या तीन थी। उन्होंने बताया कि

आईसीयू में लगभग 13 से 15 मरीजों का इलाज चल रहा था, जिन्हें उनके परिजन अन्य अस्पतालों में ले गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा, "हम मरीजों के परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। आग पर काबू पा लिया गया है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।" 'प्रसाद अस्पताल' के प्रशासन के अनुसार, प्रारंभिक तौर पर आंशका है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और तेजी से फैल गई, जिससे आईसीयू में धुआं भर गया एवं मरीजों को बाहर निकालने में काफी कठिनाई हुई। लापरवाही के सवाल पर नगर आयुक्त ऋतुराज सिंह ने पत्रकारों से कहा कि जिलाधिकारी ने मामले की गहन जांच के लिए अपर समाहर्ता (एडीएम), अनुमंडल अधिकारी (एसडीएम), अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) एवं अन्य अधिकारियों की पांच सदस्यीय टीम गठित की है। उन्होंने कहा, "जांच दल की रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आग लगने की वास्तविक वजह क्या थी।"

चंद्रनाथ रथ हत्याकांड : वांछित गैंगस्टर ने बलिया की अदालत में आत्मसमर्पण किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बलिया/भाषा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा आरोपियों की तलाश के लिए चलाये गये अभियान के बीच एक वांछित गैंगस्टर ने बृहस्पतिवार को एक स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने बताया कि ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोनू ने बलिया की एक अदालत के सामने एक पुराने मामले में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए मजिस्ट्रेट ने स्थानांतरित कर दिया गया। बांसडीह रोड थानाध्यक्ष वंश बहादुर सिंह ने बताया कि सिंह पर 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में भी वांछित था। उन्होंने बताया कि साल 2023 में

बांसडीह रोड थाने में सिंह के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। सिंह के वकील कैश सिंह ने बताया कि गैंगस्टर अदालत के न्यायाधीश हरीश कुमार ने ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि अदालत ने 25 मई को सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था क्योंकि वह इस मामले में अदालत के सामने पेश नहीं हुआ था। अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि सीबीआई के अधिकारी सिंह पर आत्मसमर्पण करने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे और जांच के सिलसिले में हाल ही में उन्होंने सिंह के घर से सीसीटीवी फुटेज भी जब्त की थी। इस बीच, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी महिमा सिंह ने कहा कि उसका पति निर्दोष है। महिमा ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, मेरे पति को हत्या के झूठे मामले में फंसाया गया है। हमें सीबीआई पर पूरा भरोसा है और हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है।

बिहार के पुलों का नियमित सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण सुनिश्चित करें अधिकारी : समाट चौधरी

पटना/भाषा। बिहार के मुख्यमंत्री

समाट चौधरी ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि पुलों का विशेषज्ञों के माध्यम से नियमित सुरक्षा ऑडिट (सेफ्टी ऑडिट) और निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के बयान के अनुसार, चौधरी ने कहा कि सड़क और पुल निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "लोगों को सुरक्षित, सुगम और उच्च गुणवत्ता वाला सड़क संपर्क उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।" मुख्यमंत्री ने सड़क एवं पुल निर्माण तथा उनके रखरखाव के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए कहा कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जानी चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने मुंगेर-बड़ियापुर-घोरघाट-सुल्तानगंज-भागलपुर-सबौर फोरलेन गा पथ परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। यह परियोजना 'हाइब्रिड एन्युटी मॉडल' (एचएएम) के तहत क्रियान्वित की जाएगी। चौधरी ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी बिहार में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी तथा क्षेत्र के आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में बिहार के पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रवच्य अमृत, सड़क निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



मथुरा में बच्ची को अगवा कर रमथान में उसके साथ किया गया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मथुरा (उप्र)/भाषा। मथुरा जनपद के एक गांव में एक युवक अपनी मां के पास सो रही एक बच्ची को कथित तौर पर उठाकर रमथान ले गया और कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि बेहोश हो जाने पर बच्ची को वहीं छोड़कर वह भाग गया तथा बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। छाता क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक भूपण वर्मा ने बताया कि बुधवार रात एक युवक खिड़की तोड़कर घर घुस गया और मां के पास सो रही सात साल की बच्ची को उठाकर ले गया। वर्मा के अनुसार बच्ची हल्ला न मचा पाए इसके लिए आरोपी ने उसका हाथ से बंद कर दिया। इस दौरान उसका पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य दूरसे कमरे में सो रहे थे। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि तड़के चार बजे जब उसकी मां जगी तो उसने बच्ची को गायब पाया तथा काफी दूढ़ने के बाद बच्ची रमथान में बेहोश पड़ी मिली। वर्मा के अनुसार होश में आने पर बच्ची ने मांबाप को बताया कि राहुल उसे जबर्जस्ती उठा ले गया और उसके साथ गंदा काम किया।

राहुल गांधी भारत की स्थिरता और सुरक्षा के खिलाफ काम कर रहे हैं : भाजपा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस दावे पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद पर नहीं रहेंगे। भाजपा ने राहुल पर देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। सत्तारूढ़ पार्टी ने यह भी दावा किया कि राहुल केवल एक बार आपातकाल लगाया गया था और वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया था कि मोदी एक साल के



मानसिकता को दर्शाती हैं। पूनावाला ने एक वीडियो बयान में कहा, "राहुल गांधी ऐसे परिवार से आते हैं, जिसका इतिहास आपातकाल से जुड़ा रहा है। इसलिए उन्हें लगता है कि हर कोई आपातकाल लगाने वाला है। भारत में संविधान को केवल एक बार कुचला गया था और वह इंदिरा गांधी ने किया था। उन्होंने जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया और उनमें हस्तक्षेप किया, वह सर्ववैदित है।" भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि वारस्तविक "आपातकाल" कांग्रेस पार्टी के भीतर है। उन्होंने कहा, "लोकतंत्र के उजर वंशवाद को रखने वाले राहुल आज भी हर जगह आपातकाल देखते हैं। एक तरह का आपातकाल जरूर है, लेकिन वह कांग्रेस के भीतर है।"

मुख्यमंत्री संगमा ने अमित शाह के समक्ष आईएलपी, खासी और गारो भाषा की मान्यता का मुद्दा उठाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

शिलांग/भाषा। मेघालय सरकार ने खासी और गारो भाषाओं की संवैधानिक मान्यता और आईएलपी के लिए अपने प्रयासों को फिर से तेज कर दिया है और मुख्यमंत्री कोणराड के संगमा ने बृहस्पतिवार को यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष इन मुद्दों को उठाया। यहां उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) की 73वीं पूर्ण बैठक के दौरान प्रस्तुत ज्ञापन में राज्य सरकार की चार प्रमुख चिंताओं को उठाया गया जिनमें अवैध प्रवासन, संविधान की आठवीं अनुसूची में खासी और गारो को शामिल करना, छठी अनुसूची में प्रस्तावित संशोधन और विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) में बदलाव शामिल हैं। संगमा ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में अवैध प्रवासन पर चिंता

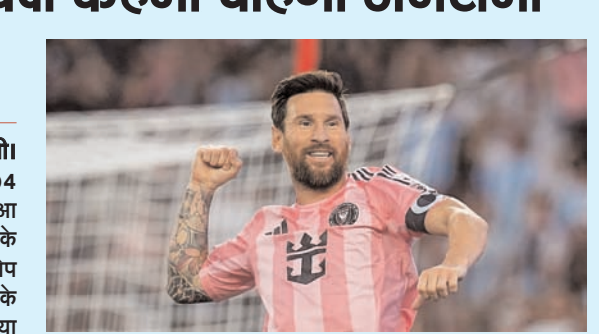


की आठवीं अनुसूची में खासी और गारो भाषाओं को शामिल करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह की मान्यता राज्य के स्वदेशी समुदायों की भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और मजबूत करने में मदद करेगी। छठी अनुसूची के मुद्दे पर संगमा ने केंद्र से अनुरोध किया कि प्रस्तावित संशोधनों पर आगे बढ़ने से पहले सभी संबंधित राज्यों के साथ परामर्श किया जाये।

एक और विश्व खिताब के साथ मेस्सी युग को विदा कहना चाहेगा अर्जेटीना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

ब्यूनस आयर्स/एपी। अमेरिका में पिछली बार 1994 में जब फुटबॉल विश्व कप हुआ था तब गुप चरण के दूसरे मैच के बाद डिगो माराडोना को डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाये जाने के बाद टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था। अर्जेटीना फुटबॉल टीम की अमेरिका की यादें सुखद नहीं हैं चूंकि उसके बाद माराडोना फिर विश्व कप नहीं खेल सके और उनकी टीम अंतिम 16 से बाहर हो गई। बाईस बरस बाद अब अर्जेटीना को उम्मीद है कि माराडोना के वारिस माने जाने वाले लियोनेल मेस्सी विश्व कप में अमेरिकी संरक्षियों पर उन कड़वी यादों को जीत के जश्न में बदलेंगे। इस महीने 39 वर्ष के होने जा रहे मेस्सी का यह



आखिरी विश्व कप होगा और माना जा रहा है कि अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होने वाले इस टूर्नामेंट के बाद वह फुटबॉल को अलविदा कह देंगे। अगर मेस्सी और अर्जेटीना विश्व कप खिताब को बरकरार रख पाते हैं तो 1982 में ब्राजील के बाद यह कारनामा करने वाली पहली टीम होगी। मेस्सी ने अर्जेटीना के एक पत्रकार को कहा था, "मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है और जब तक खेल सकता हूँ, खेलता रहूँ। मुझे जीतना पसंद है। मैं

कई बार अपने बच्चों को वीडियो गेम में भी जीतने नहीं देता। यह मेरा स्वभाव है और इसी के बल पर मैंने इतना कुछ पाया है।" बार्सिलोना, पेरिस सेंट जर्मेन और इंटर मियामी के लिये करीब दो दशक तक खेल चुके मेस्सी का शरीर अब थकने लगा है। रिकार्ड छठी बार विश्व कप खेलेने से पहले वह जांच की मांसपेशियों में खिंचाव से जूझ रहे थे। इसकी वजह से इंटर मियामी के आखिरी मैच के दौरान उन्हें मैदान से जाना पड़ा।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

आपके पास शक्ति है तो उसका दुरुपयोग होना स्वाभाविक : इजराइली राजदूत

नई दिल्ली/भाषा। भारत में नियुक्त इजराइली राजदूत रुयेन अजारा ने इजराइली रक्षा बलों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त किये जाने के आरोपों के जवाब में कहा है कि जब आपके पास शक्ति होती है, तो उसका दुरुपयोग होना स्वाभाविक है। उन्होंने आलोचना को स्वीकार करते हुए अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर उनके देश के लिए असंभव मानक निर्धारित करने का आरोप भी लगाया। सैन्य आचरण का स्पष्ट आकलन करते हुए, उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं अपवाद हैं और देश की विधि व्यवस्था के माध्यम से इनका समाधान किया जाता है। राजदूत ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और मीडिया के कुछ वर्गों पर भी आरोप लगाया कि वे क्षेत्र में अन्य पक्षों द्वारा किये गए अत्याचारों को अनदेखा करते हुए इजराइल के लिए असंभव मानक निर्धारित कर रहे हैं। अजारा ने 'पीटीआई-वीडियो' से कहा, कोई भी देश और कोई भी सेना दुर्घटनाग्रस्त करेगी। जब आपके

पास शक्ति होती है, तो उसका दुरुपयोग होना स्वाभाविक है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल की विधि व्यवस्था सैनिकों को जवाबदेह ठहराने के लिए सक्रिय रूप से काम करती है, भले ही आलोचकों का तर्क हो कि (इजराइल) सरकार कुछ मामलों में बहुत नरम रही है। उनसे जब फ्लैग्समैन बंदियों के साथ दुर्घटनाग्रस्त होने वाले आरोपी सैनिकों के खिलाफ इजराइली अधिकारियों द्वारा आरोप वापस लिये जाने के बारे में पूछा गया, तो अजारा ने तर्क दिया कि तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का एक सफल प्रयास किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इजराइल को लगातार आरोपी के रूप में दर्शाया जाए। अजारा ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी पेशेवर सैन्य अधिकारी के लिए सबसे अहम सवाल यह है कि दुर्घटनाग्रस्त अपवाद है या नियम, और क्या ऐसी घटनाओं के होने पर अधिकारी

सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं। राजदूत ने विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र को निशाना बनाते हुए दावा किया कि अधिकांश अरब और मुस्लिम देश संयुक्त राष्ट्र का उपयोग उन लोगों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं जिन्हें इजराइल ने पूरी तरह से पक्षपात करने वाला करार दिया हुआ है। उन्होंने इन लोगों द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों को इजराइल के खिलाफ मीडिया में नकारात्मक भावना गढ़ने के लिए बनाये गए तंत्र का हिस्सा बताया। हाल में, इजराइल को पहली बार संयुक्त राष्ट्र की उस काली सूची में शामिल किया गया है, जो संघर्ष क्षेत्रों में यौन हिंसा करने वाले देशों से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेर्रेस के कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र ने गाजा और वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के खिलाफ इजराइली सेना द्वारा कथित तौर पर किये गए यौन हिंसा के 31 मामलों की पुष्टि की है।

अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 'द सेकंड ऑर्बिट' के साथ लेखक बने

नई दिल्ली/भाषा। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा करने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला अब लेखक बनने जा रहे हैं। उनकी किताब 'द सेकंड ऑर्बिट: बिलीफ ऑफ ए मैनड्रीम ऑफ 1.4 बिलियन हार्ल्स 25 जून को बाजार में उपलब्ध होगी। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (पीआरएचआई) द्वारा प्रकाशित संस्करण में ग्रुप कैप्टन शुक्ला मानव अंतरिक्ष उड़ान की वास्तविकताओं को साझा करते हैं। इसमें उन्होंने अंतरिक्ष उड़ान की वास्तविकताओं का वर्णन किया है, जिसमें वर्षों की तैयारी, असफलताएं, अनुशासन, कठोर प्रशिक्षण, अनिश्चितताएं और उस सपने को पूरा करने के लिए जरूरी अटूट विश्वास शामिल है, जो अक्सर असंभव प्रतीत होता था। शुक्ला उन चार अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थे, जिन्होंने पिछले साल जून में अंतरिक्ष यात्री की ओर नारा के एक्सिओम-4 मिशन के तहत आईएसएस पर 18 दिन बिताए। यह उपलब्धि चार दशक बाद किसी भारतीय की अंतरिक्ष में यापसी का प्रतीक बनी। इससे पहले वर्ष 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। शुक्ला ने अपनी किताब में लिखा है, उड़ान से पहले ही मैं एक सवाल के साथ कैमरूल में गया—इस मिशन का अर्थ क्या होना चाहिए? एक अंतरिक्ष उड़ान भविष्य की तकनीकों के द्वार खोलती है, लेकिन



इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह एक ऐसी भावना को जन्म देती है जिसे मापना कठिन है—किसी बच्चे के मन में यह विश्वास जगाना कि उसके लिए संभावनाओं का एक नया दरवाजा खुल गया है। अशोक चक्र से सम्मानित शुक्ला ने एक बयान में कहा, 42 वर्ष पहले राकेश शर्मा ने मेरी पीढ़ी सहित पूरे एक दौर के लिए उस दरवाजे को खोला था। यह पुस्तक उस दरवाजे को अगली पीढ़ी के लिए खुला रखने का मेरा एक प्रयास है। रोचक किस्तों और दुर्लभ प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से शुक्ला पाठकों को अंतरिक्ष यात्री चयन प्रक्रिया, वर्षों के कठिन प्रशिक्षण, आईएसएस पर बिताए गए जीवन और यहां तक पहुंचने की यात्रा से रूबरू करवाएंगे। प्रकाशकों के अनुसार, 'द सेकंड ऑर्बिट' केवल अंतरिक्ष की कहानी नहीं है। यह आत्मविश्वास, उड़ पर काबू पाकर अवसरों को स्वीकार करने और 1.4 अरब भारतीयों की उम्मीदों को पृथ्वी के वायुमंडल से परे ले जाने की प्रेरक यात्रा की कहानी है।

लांचिंग



बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा मुंबई में आयोजित लज्जरी ज्वेलरी के भव्य लॉन्चिंग इवेंट में अपने पति जीन गुडइनफ के साथ शामिल हुईं।

जब हैसियत बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं : कंगना रनौत

मुंबई/एजेन्सी

फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों रणवीर सिंह और फिल्म फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉयज (एफडब्ल्यूआईसीई) के बीच चल रहा विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। अभिनेता के खिलाफ जारी किए गए नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव को लेकर कई कलाकार अपनी-अपनी राय रख रहे हैं। इसी बीच अब अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। कंगना रनौत ने अपनी आने वाली फिल्म 'भारत भाय विधाता' के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम के दौरान रणवीर सिंह के समर्थन में बात करते हुए कहा कि जब हैसियत बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं। ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान जब कंगना रनौत से रणवीर सिंह और उनके खिलाफ जारी किए गए फेडरेशन के फैसले को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, "मुझसे इस विषय पर सवाल पूछना दिलचस्प है। मुझे भी सभी ने बैन किया था। जब आपकी हैसियत बढ़ती है, तो दुश्मन भी बढ़ते हैं।



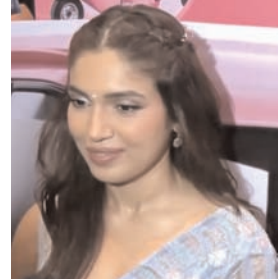
एसा नामुमकिन है कि आपकी हैसियत बढ़े और दुश्मन न बढ़े। ऐसे में रणवीर सिंह को समझना चाहिए कि उनकी क्या हैसियत है, जो उनके इतने दुश्मन हैं।" कंगना ने आगे कहा, "जीवन में हमेशा एक जैसे हालात नहीं रहते। सफलता के साथ संघर्ष भी आते हैं। मेरे साथ भी फिल्म इंडस्ट्री में कई तरह की घटनाएं हुईं, लेकिन मैंने काम करना नहीं छोड़ा। मैं अच्छा कर रही हूँ, मेरे करियर की गाड़ी अच्छी चल रही है। ऐसे फैसलों से कुछ फर्क नहीं पड़ता।" दरअसल, पूरा मामला फिल्म 'डॉन 3' से जुड़ा हुआ है। इस फिल्म की

घोषणा साल 2023 में फिल्म निर्माता फरहान अख्तर ने की थी। फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका निभाने वाले थे और इसे लोकप्रिय डॉन फ्रेंचाइजी की अगली कड़ी माना जा रहा था। हालांकि बाद में खबरें सामने आई कि रणवीर सिंह ने फिल्म से खुद को अलग कर लिया है। इसके बाद विवाद शुरू हुआ और मामला अलग-अलग संगठनों तक पहुंच गया। फिल्म निर्माताओं का आरोप है कि फिल्म की तैयारी, प्री-प्रोडक्शन और शेड्यूल में बदलाव के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसे में एफडब्ल्यूआईसीई ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी किया। फेडरेशन का कहना था कि जब तक मामला नहीं सुलझता, तब तक उससे जुड़े सदस्य रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेंगे। हालांकि इस फैसले को लेकर इंडस्ट्री के कई लोगों ने अलग-अलग राय रखी है। चंकी पांडे और मनोज बाजपेयी समेत कई सितारों ने उम्मीद जताई कि यह विवाद बातचीत के जरिए जल्द सुलझ जाएगा।

भूमि पेडनेकर ने किया 'पिक ई-रिवशा' पहल का समर्थन, कहा- इससे महिलाओं की जिंदगी में आएगा बदलाव

मुंबई/एजेन्सी

मुंबई में 'ड्राइव हर फ्यूचर' नाम से एक पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार देना, उन्हें आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस अभियान के तहत शुरू की गई 'पिक ई-रिवशा' पहल को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने अपना खुलकर समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि जब महिलाओं को कमाने और अपने पैरों पर खड़े होने का मौका मिलता है, तो न सिर्फ उनका जीवन बदलता है, बल्कि पूरे समाज और देश की प्रगति भी तेज हो जाती है। मुंबई में आयोजित लॉन्च कार्यक्रम के दौरान भूमि पेडनेकर ने इस पहल की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, "यह पहल पर्यावरण, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण इन तीनों मुद्दों को एक साथ जोड़ती है। अक्सर लोग महिला सशक्तिकरण की बातें तो करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे कदम देखने को मिलते हैं जो वास्तव में महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लाएं। यह एक ऐसा काम है जो महिलाओं को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाएगा।" भूमि पेडनेकर ने कहा, "इस कदम के तहत महिला चालकों को ई-रिवशा दिए जाएंगे, जिससे वे खुद रोजगार कमा सकेंगी। आर्थिक स्वतंत्रता किसी भी महिला को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। जब किसी महिला के पास अपनी आय का स्रोत होता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने फैसले खुद लेने में सक्षम बनती है। अगर देश की महिलाएं सक्षम और आत्मनिर्भर होंगी, तो देश की विकास गति भी तेज होगी और समाज में सुरक्षा का माहौल भी बेहतर बनेगा।" अभिनेत्री ने आगे कहा, "इस पहल की सबसे खास बात यह है कि यह केवल महिलाओं के लिए अक्सर



पेदा नहीं कर रही, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रही है। मुंबई में शुरुआत के तौर पर एक हजार 'पिक ई-रिवशा' लॉन्च किए जा रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में कुल 12 हजार ई-रिवशा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। भविष्य में इस योजना को अन्य राज्यों तक भी पहुंचाया जाएगा, ताकि देशभर की महिलाओं को इसका लाभ मिल सके।" इस कार्यक्रम में भूमि पेडनेकर के साथ अमृता फडणवीस और साहेर भामला भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अमृता फडणवीस ने भी इस पहल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के सामने पर्यावरण संरक्षण सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ऐसे समय में इलेक्ट्रिक याहनों को बढ़ावा देना बेहद जरूरी हो गया है। 'पिक ई-रिवशा' योजना महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता तो देती ही है, साथ ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी मदद करती है। जब एक महिला ई-रिवशा चलाकर अपनी आजीविका कमाती है, तो वह समाज और पर्यावरण दोनों के लिए सकारात्मक योगदान देती है। गौरतलब है कि भामला फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई 'ड्राइव हर फ्यूचर' पहल का उद्देश्य एक हजार महिलाओं को ई-रिवशा उपलब्ध कराना है। इस पहल के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

पूजा अर्चना



ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता के ऐतिहासिक कालीघाट मंदिर में जाकर दर्शन किए और विशेष पूजा-अर्चना की।

प्रदूषण नहीं रुका तो खो जाएगी दुनिया की खूबसूरती : शुभांगी अत्रे

मुंबई/एजेन्सी



टीवी जगत की मशहूर अभिनेत्री शुभांगी अत्रे ने पर्यावरण को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने पर्यावरण से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की और कहा कि अगर इसांनों ने अब भी अपनी आदतों में बदलाव नहीं किया, तो आने वाले समय में प्रकृति का संतुलन गंभीर रूप से बिगड़ सकता है। आईएसएस से बात करते हुए शुभांगी अत्रे ने कहा, "आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसांन प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना भूल गया है। पहले लोग प्रकृति का उपयोग अपनी जरूरतों के अनुसार करते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका असर धरती के हर हिस्से पर दिखाई देने लगा है।" शुभांगी ने कहा,

"इसांन अब सिर्फ संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहा, बल्कि उन्हें तेजी से खत्म भी कर रहा है। जंगल लगातार कम होते जा रहे हैं, जिसके कारण जानवरों का प्राकृतिक आवास छिन रहा है। कई प्रजातियां संकट में हैं और मौसम का चक्र भी पहले जैसा नहीं रहा। कभी अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो कभी अचानक भारी बारिश हो जाती है। यह सब प्रकृति के असंतुलन का संकेत है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।" अभिनेत्री ने प्लास्टिक प्रदूषण को भी एक गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा, "प्लास्टिक ऐसा जहर है जो धीरे-धीरे पूरी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक धरती और जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहा है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन जीव-जंतुओं को होता है, जो यह समझ ही नहीं पाते कि यह उनके लिए कितना खतरनाक है। कई बार जानवर प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेते हैं, जिससे उनकी जान तक चली जाती है। इसे कम करने के लिए लोगों को अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव लाना होगा। अगर प्रदूषण नहीं रुका तो दुनिया अपनी प्राकृतिक शांति खो देगी।" उन्होंने कहा,

"पर्यावरण की रक्षा रोजाना छोटे-छोटे प्रयासों से की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा रहता है, तो वह जीवनशैली के प्रति ज्यादा जिम्मेदार होता है। यही जुड़ाव लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाता है और उन्हें सही विकल्प चुनने की प्रेरणा देता है।" विश्व पर्यावरण दिवस से पहले शुभांगी ने भविष्य को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "अगर प्रदूषण इसी तरह बढ़ता रहा तो दुनिया अपनी प्राकृतिक शांति और खूबसूरती खो सकती है। प्रकृति केवल पेड़-पौधों या नदियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इसांनों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। अगर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो इसांन भी स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी पाएगा।" शुभांगी अत्रे ने लोगों से अपील की कि वे अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में कुछ समय प्रकृति को समझने और उसके महत्व को महसूस करने के लिए निकालें। हर घंटा की सम्मान करना सीखना होगा। अगर हम धरती, पेड़-पौधों, नदियों और जीव-जंतुओं की रक्षा करेंगे, तो प्रकृति ही हमें सुरक्षित और संतुलित जीवन देती रहेगी।

पाकिस्तान बना रहा नई आंतरिक सुरक्षा नीति, आतंकवाद के वित्तपोषण रोकने पर जोर

इस्लामाबाद/भाषा। पाकिस्तान एक नई आंतरिक सुरक्षा नीति पर काम कर रहा है, जिसका मकसद आपराधिक डेटाबेस को एकीकृत करके और प्रांतों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था सुधारकर आतंकवाद के वित्तपोषण पर लगाव लगाना है। प्रस्तावित राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा नीति 2026-30 पर इसी महीने नेशनल पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड (एनपीएमबी) की एक असाधारण बैठक में चर्चा होगी और इसमें सभी प्रांतीय पुलिस प्रमुखों की सिफारिशें शामिल की जाएंगी। 'डॉन' अखबार की खबर में बृहस्पतिवार को कहा गया कि इसमें पाकिस्तान के कच्चे तेल कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के पुलिस

प्रमुखों के सुझाव भी लिए जाएंगे। खबर के अनुसार प्रस्तावों में गिलगित-बाल्टिस्तान में 'काउंटर-टेरिस्ट्रि डिपार्टमेंट' (सीटीडी) की स्थापना, राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस डेटा का एकीकरण, अंतर-प्रांतीय खुफिया साझाकरण तंत्र में सुधार और आतंकवाद के वित्तपोषण रोकने के उपाय शामिल हैं। इस नीति में राष्ट्रीय पुलिस ब्यूरो (एनपीबी) के देशव्यापी पुलिस सुधारों और सुरक्षा रणनीतियों में बड़ी भूमिका की परिकल्पना की गई है। ब्यूरो की अध्यक्षता फिलहाल संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के महानिदेशक उस्मान अनवर कर रहे हैं। अनवर ने 'डॉन' से कहा कि विभिन्न असेंज कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के बीच गंभीर तालमेल की कमी है। उन्होंने पूरे देश में पुलिस

व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी प्रांतों में एक समान पुलिसिंग तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आतंकवाद से लड़ने और आतंकी वित्तपोषण पर लगाव लगाने के लिए प्रांतों में एकसमान तंत्र स्थापित करना और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अनवर ने बताया कि आगामी बैठक में कार्यात्मक विशेषज्ञता, पुलिस कल्याण, अंतरराष्ट्रीय अपराध, आपराधिक डेटा एकीकरण, प्रशिक्षण जरूरतें, महिला पुलिस नेटवर्किंग, अंतर-प्रांतीय खुफिया साझाकरण और गिलगित-बाल्टिस्तान में सीटीडी के विकास पर भी चर्चा होगी।

स्वागत



लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला स्थित पंतनगर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर कांग्रेस विधायक मोहम्मद निजामुद्दीन और उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

5 साल की उम्र में मिली जिम्मेदारियां, स्कूल की जगह फिल्मों के सेट पर बीता था सारिका का बचपन

मुंबई/एजेन्सी



फिल्मी दुनिया में अभिनेत्री सारिका ने बचपन में ही जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर ले लिया था। जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं और अपने सपने बुनते हैं, उस उम्र में सारिका को परिवार का सहारा बनना पड़ा। यही संघर्ष आगे चलकर उनकी पहचान बना और उन्होंने अपने दम पर हिंदी सिनेमा में एक खास मुकाम हासिल किया। अभिनय से लेकर कॉस्ट्यूम डिजाइन तक, उन्होंने कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाई और राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। सारिका का जन्म 3 जून 1960 को नई दिल्ली में हुआ था। जब वह छोटी थीं, तब उनके पिता परिवार से अलग हो गए थे। ऐसे में सारिका को महज पांच साल की उम्र में ही काम करना पड़ा। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने फिल्मों में काम शुरू किया। इसी वजह से वह स्कूल नहीं जा सकीं। हालांकि पढ़ाई का मौका कम मिला, लेकिन उन्होंने जिंदगी से बहुत कुछ सीखा और मेहनत को अपना सबसे बड़ा सहारा बनाया।

के बीच लोकप्रिय रहीं। सारिका का निजी जीवन भी अक्सर चर्चा में रहा। उनका नाम अभिनेता कमल हासन के साथ जुड़ा। दोनों लंबे समय तक लिव-इन में रहे और बाद में शादी कर ली। उनकी दो बेटियां हैं, जिनमें श्रुति हासन आज फिल्म जगत का जवाना है। श्रुति हासन का जन्म शादी से पहले हो गया था। उसके बाद अक्षरा हासन का जन्म हुआ। साल 1988 में कमल हासन और सारिका ने शादी की और 2004 में अलग हो गए। अभिनय के अलावा सारिका ने पढ़ने के पीछे भी कई काम किया। उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाई। फिल्म 'हे राम' के लिए उनके काम को काफी सराहना मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके बाद फिल्म 'परजानिया' में उनके मददार अभिनय ने सभी का ध्यान खींचा। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला।

मुख्यमंत्री शिवकुमार के सामने 2028 चुनाव की तैयारी के साथ कई मोर्चों पर चुनौतियां

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बंगलूर। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के सामने कांग्रेस को 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही उन्हें राजनीतिक, वित्तीय और प्रशासनिक मोर्चों पर कई चुनौतियों का भी सामना करना होगा। 64 वर्षीय शिवकुमार ने ऐसे समय में राज्य की कमान संभाली है जब कर्नाटक विभिन्न स्तरों पर जटिल चुनौतियों से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में उनके सामने पहली बड़ी चुनौती मंत्रिमंडल का गठन और विभागों का बंटवारा है। उन्होंने बुधवार को पहले चरण में 13 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सहित कुल 34 मंत्रियों की स्वीकृत संख्या है। मंत्रिमंडल के कई दावेदारों और सीमित रिक्तियों के बीच शिवकुमार को संतुलन बनाना होगा। नए मंत्रिमंडल में उन्हें जातीय समीकरणों, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या के समर्थकों को ध्यान में रखते हुए समावेशी संतुलन बनाना पड़ेगा। सिद्धरामय्या के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद कांग्रेस के लिए 'अहिंदा' वोट बैंक को बनाए रखना भी शिवकुमार के लिए महत्वपूर्ण चुनौती होगी। 'अहिंदा' अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए कन्नड़ भाषा का संक्षिप्त रूप है। सिद्धरामय्या को इन समुदायों का मजबूत समर्थक माना जाता है और 2023 के विधानसभा चुनाव में इन वर्गों का कांग्रेस के पक्ष में व्यापक समर्थन पार्टी की सत्ता में



वापसी का प्रमुख कारण रहा था। आगामी चुनावों में भी इन वर्गों का समर्थन कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिवकुमार को सिद्धरामय्या और उनके समर्थकों को विधायकों में लेकर आगे बढ़ना होगा, साथ ही राज्य के प्रभावशाली समुदायों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राज्य के दूसरे बड़े प्रभावशाली समुदाय वीरशैव-लिंगायत उनके किसी फसले से नाराज न हों। वीरशैव-लिंगायत की उत्तर कर्नाटक और दक्षिण के कुछ हिस्सों में मजबूत उपस्थिति है।

विभिन्न समुदायों के बीच संतुलन साधने की उनकी क्षमता की बड़ी परीक्षा उस समय होगी जब सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी जिसे आम तौर पर 'जाति जनगणना' कहा जाता है। लिंगायत और वोक्कालिगा जैसे प्रभावशाली समुदायों ने पहले की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताई थी और शिवकुमार ने स्वयं भी उस पर संदेह व्यक्त किया था। कांग्रेस के भीतर कई नेताओं का मानना है कि शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने से पुराने मैसूर क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले वोक्कालिगा

समुदाय का समर्थन पार्टी के पक्ष में और मजबूत हो सकता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में वोक्कालिगा समुदाय के एक हिस्से का कांग्रेस की ओर झुकाव इस उम्मीद से जुड़ा माना गया था कि शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि भाजपा और जनता दल (एस) के गठबंधन के बीच इस समर्थन को बनाए रखना भी उनके लिए बड़ी चुनौती होगी।

वोक्कालिगा समुदाय का एक बड़ा वर्ग पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौडा और उनके पुत्र तथा केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी को अब भी सम्मान की दृष्टि से देखता है। यह समुदाय जद (एस) का पारंपरिक समर्थन आधार माना जाता है। राज्य की वित्तीय स्थिति का प्रबंधन भी शिवकुमार के लिए एक अहम चुनौती होगी। लोकलुभावान गारंटी योजनाओं पर बढ़ते खर्च के कारण सरकारी ऋण बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 में सरकार ने पांच गारंटी योजनाओं के लिए 51,286 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। शिवकुमार पहले ही इन योजनाओं के लाभाधिकारों की सूची की समीक्षा करने की बात कह चुके हैं, क्योंकि इनके दुरुपयोग को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। बढ़ते कर्ज और सस्किडी के बोझ को लेकर चिंता बनी हुई है, जबकि कल्याणकारी योजनाओं में किसी प्रकार की कटौती जन असंतोष को जन्म दे सकती है। सामान्य से कम मानसून की आशंकाओं के बीच संभावित कृषि संकट, विकास परियोजनाओं की धीमी प्रगति, पिछड़े जिलों की समस्याओं का समाधान तथा लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना भी प्रमुख चुनौतियों में शामिल है।



पौधारोपण

हुब्ली धारवाड महानगर पालिका के वार्ड क्रमांक 4.4 की पार्श्व उमा मुकुंद के जन्मदिवस के अवसर पर गुरुवार को हुब्ली स्थित मधुरा एस्टेट गार्डन में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा मध्य विधानसभा क्षेत्र मंडल 73 के सचिव विनोदकुमार पटवा, मुकुंद कुमार तथा निखिल वांगी ने पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

भारतीय सेना के मेजर ने अमेरिकी सेना के उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दो पुरस्कार जीते

वाशिंगटन/भाषा। भारतीय सेना के एक मेजर ने फोर्ट लेवेनवर्थ, कैंसास में आयोजित एक प्रतिष्ठित अमेरिकी सेना नेतृत्व कार्यक्रम में दो शैक्षणिक पुरस्कार जीते हैं, जिसमें अमेरिका और सहयोगी देशों के 951 अधिकारी शामिल थे। अमेरिकी सेना के 'कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज' के 'कमांड एंड जनरल स्टाफ ऑफिसर कोर्स' (सीजीएसओसी) के दीक्षांत समारोह के दौरान भारत के मेजर प्रभात मिश्रा को उत्कृष्ट 'मास्टर ऑफ मिलिट्री आर्ट्स एंड साइंस थिसिस' के लिए 'बिर-ब्रूक्स' पुरस्कार और 'जनरल डगलस मैकआर्थर मिलिट्री लीडरशिप राइटिंग अवार्ड' से सम्मानित किया गया।

ये पुरस्कार 951 स्नातकों को प्रदान किए गए जिन्होंने 10 महीने का कार्यक्रम पूरा किया। स्नातक होने वालों में 92 देशों के 120 अंतरराष्ट्रीय सैन्य छात्र शामिल थे। अमेरिकी सेना के एक बयान में कहा गया कि इस वर्ष के बीच ने संशोधित और आधुनिक पाठ्यक्रम का अध्ययन किया। अन्य अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों में नॉर्वे के मेजर अलेक्जेंडर ग्रैनवर्ग को जनरल स्टाफ डी. आइजनहावर पुरस्कार और आर्दर-डॉनिकान पुरस्कार प्राप्त हुआ। कुवैत के लेफ्टिनेंट कर्नल तालेह एब एफ एच एच अलराशिद को मेजर जनरल हंस स्लूप पुरस्कार मिला। फोर्ट लेवेनवर्थ में अंतरराष्ट्रीय सैन्य शिक्षा की शुरुआत 1894 में हुई थी। तब से, लगभग 170 देशों के 8,700 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सैन्य छात्रों ने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ कक्षाओं में भाग लिया है।

नई पार्टी या इस्तीफे पर बात नहीं हुई : अन्नामलाई मुद्दे पर भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष



दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

तिरुनेलवेली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष नैरान नार्गेन्द्र ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनके पूर्ववर्ती के अन्नामलाई ने नयी पार्टी बनाने के बारे में किसी से कोई बात नहीं की है। नार्गेन्द्र ने यह भी कहा कि उन्हें पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से कोई व्यापक बात नहीं हुई है। अन्नामलाई के भाजपा छोड़कर अपनी नयी पार्टी बनाने की अटकलों के बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नार्गेन्द्र ने स्पष्ट किया कि उनके (अन्नामलाई) इस्तीफे की खबरें निराधार हैं। नार्गेन्द्र ने पत्रकारों से कहा, "भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे अभी तक ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। अन्नामलाई ने किसी से भी नयी पार्टी बनाने के बारे में बात नहीं की है। इस बारे में हमारी उनसे बात नहीं हुई है ना ही उन्होंने हमसे कुछ कहा है।" अन्नामलाई के इस्तीफे को लेकर अटकलों के बारे में पूछे जाने पर नार्गेन्द्र ने कहा, "आज भरे प्रिय भाई (अन्नामलाई) को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके इस्तीफे की खबरें झूठी, निराधार और अफवाहें हैं।" भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी अन्नामलाई ने राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। यह मुलाकात ऐसे समय हुई, जब उनके भाजपा छोड़कर अपनी नयी राजनीतिक पार्टी बनाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि, पार्टी ने आधिकारिक तौर पर यह खुलासा नहीं किया है कि बैठक में क्या चर्चा हुई।



भोजपुरी सेवा समिति का पिकनिक कार्यक्रम एवं स्वच्छता अभियान संपन्न

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बंगलूर। भोजपुरी समाज सेवा समिति के 61 सदस्यीय दल ने सामाजिक एकता, सद्भावना, आपसी मेल-मिलाप एवं भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उडुपी का भ्रमण किया। इस कार्यक्रम का अन्य उद्देश्य युवा वर्ग को दक्षिण भारत की सभ्यता, संस्कृति एवं भौगोलिक विशेषताओं से परिचित कराना तथा समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना भी था। समिति के संस्थापक अध्यक्ष एवं चेयरमैन संजय सिंह ने बताया कि सदस्य दल ने श्री कृष्ण मठ, दुर्गा परमेश्वरी मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन किए। भ्रमण के दौरान समिति द्वारा स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। सदस्यों ने मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों की सफाई की तथा लोगों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया।



जीतो स्वयं-वी कनेक्ट की बैठक में 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' पर हुआ विशेष प्रशिक्षण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बंगलूर। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (जीतो) बंगलूर नार्थ लेडीज विंग के व्यावसायिक समूह स्वयं-वी कनेक्ट की बैठक आयोजित हुई।

रेफरल प्रमुख सीए सुखदेवी जैन, रेफरल लीड प्रजा सेठी एवं रेफरल सचिव मोक्षा सोलंकी

शामिल थीं। बैठक में नॉर्थ की लेडीज अध्यक्ष लक्ष्मी बाफना, सचिव रक्षा छाजेड एवं कोषाध्यक्ष तनुजा मेहता भी उपस्थित थीं। बैठक का मुख्य आकर्षण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) विषय पर आयोजित विशेष कार्यशाला रही, जिसका संचालन मेनइन्फिनिटी ऑटोमेशन के मुख्य प्रोग्रामिनी अधिकारी एवं एआई इंजीनियर प्रिंस जैन ने किया। उन्होंने चैट जीपीटी, जेपीपी, नोटबुक-एलएम एवं

कॉमेट जैसे आधुनिक एआई प्लेटफॉर्म का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हुए सदस्यों को तकनीक के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी।

बैठक के अंतर्गत व्यावसायिक प्रस्तुति में विभिन्न सदस्यों ने अपने अपने व्यवसाय की जानकारी दी। बैठक के दौरान विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सदस्यों को सम्मानित किया गया।



पर्यावरण दिवस पर ऊर्जा संरक्षण हेतु दो घंटे एसी बंद रखने का निवेदन

बंगलूर/दक्षिण भारत। अणुव्रत विश्व भारतीय सोसाइटी द्वारा विश्वव्यापी ऊर्जा संरक्षण अभियान के अंतर्गत विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर एक विशेष जनजागरण कार्यक्रम के तहत नागरिकों से दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक अपने घरों, कार्यालयों, प्रतिष्ठानों एवं अन्य स्थानों पर एसी बंद रखकर ऊर्जा बचत में योगदान देने का आह्वान किया गया।

उसी क्रम में अणुव्रत समिति के राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजेश चावत, विजयनगर के अध्यक्ष महेंद्र टेबा, सहमंत्री श्रीनिवास

संगठन मंत्री दक्षिण पर्यावरण प्रभारी सम्पत चावत सलाहकार एएन डगा, सभिति सदस्य नरेंद्र पोखरना, नवरतन वैद, संयोजक भूराराम सीरवी ने इस पर्यावरण संरक्षण अभियान का प्रचार किया और लोगों से सहभागिता के लिए निवेदन किया।



विचारों का टकराव हिंसा और अशांति की जननी है : राष्ट्रसंत कमलमुनि

बंगलूर/दक्षिण भारत। शहर के मागड़ी रोड स्थित ज्येष्ठ पुष्कर जैन आराधना केन्द्र में विराजित राष्ट्रसंत कमलमुनिजी कमलेश ने गुरुवार को अपने दैनिक प्रवचन में कहा कि प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति और विचारों की ऊर्जा का भंडार समाया हुआ है। सब्र के माध्यम से उसे जागृत करके उसको सही दिशा मिल जाए तो वह स्वयं के कल्याण में सहयोगी बनता है और संपूर्ण मानवता के लिए वरदान बनता

है। विचारों के माध्यम से ही व्यक्ति भगवान बनता है, इंसान बनता है और शैतान भी बनता है। जाति, पंथ, प्रांत, भाषा के संकीर्ण विचार हथियार से भी ज्यादा घातक हैं और परमाणु बम से भी खतरनाक हैं। विचारों का टकराव हिंसा और अशांति की जननी है। उन्होंने कहा कि विश्व बंधुत्व की विचारधारा जब तक विचारों में विकसित नहीं होती तब तक उसका आध्यात्मिकता और धार्मिकता में प्रवेश नहीं हो सकता।

सभी धर्मों ने यही संदेश दिया है विश्व बंधुत्व का और भाईचारे का। संतश्री ने कहा कि महापुरुषों के विचार हीरे-मोती से भी अधिक कीमती हैं, अनमोल हैं। इस मौके पर संतों के सांख्यिक में अनेक वीरगानाओं का सम्मान महिला मंडल और बहू मंडल की सदस्यों ने किया। पुष्कर भवन के महामंत्री महावीरचंद मेहता ने संचालन किया। अध्यक्ष नेमीचंद सालेचा ने धन्यवाद दिया। साध्वीश्री सत्यप्रभाजी ने मंगलाचरण किया।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत



* विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष गीत

पेड़ों से जीवन है

पेड़ों से जीवन है तुम उनको न काटना, बाँट सको तो घर-घर हरियाली बाँटना।

जलवायु दूषित होने न पाए भूल से, जहरीली गंध लगेगी आने फूल से, भूमि में अपशिष्टों को ढंग से पाटना।

ऐसी तकनीक का हर जगह प्रयोग हो, क्षतिग्रस्त हो कोई न किसी को रोग हो, पर्यावरण शुद्ध रहे वो प्रविधि छाँटना।

बच्चों की तरह पेड़ पौधों को पालना, नदी और सरोवर में कूड़े न डालना, पड़ जाएगा वरना तुम्हें धूल चाटना।

प्रकृति की रक्षा आज बेहद जरूरी है, फर्ज़ समझना, ये न कहना मजबूरी है, कोई बहकाए तो तुम उसको नाटना।

■ माणिक विश्वकर्मा 'नवरंग' मो. 9424141875

कर्नाटक मंत्रिमंडल में कोई महिला नहीं, कांग्रेस नेता मागरेट अल्वा ने जताई निराशा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बंगलूर। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मागरेट अल्वा ने मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल में महिलाओं को प्रतिनिधित्व न मिलने पर गहरी निराशा व्यक्त की है। मुख्यमंत्री शिवकुमार ने बुधवार को 13 मंत्रियों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। अल्वा ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, डी. के. शिवकुमार जी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मैं उन्हें और उनकी टीम को सफलता की शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे आज शपथ लेने वाले कर्नाटक के नए मंत्रिमंडल में कम से कम एक कांग्रेस महिला सदस्य को देखकर बेहद खुशी होती। मंत्रिमंडल में एक भी महिला को शामिल न किए जाने से मुझे गहरी निराशा हुई है। अल्वा केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं और उन्होंने कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी सेवाएं दी हैं।



बधाई

केपीसीसी के नए अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने गुरुवार को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया। शिवकुमार ने नए अध्यक्ष को पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।